पड़ा है। जरा आप बताइए कि फसल बीमा से कितने किसानों को लाभ पहुंचाया गया है ? मेरा यह सुझाव है कि आप फसल बीमा को व्यावहारिक रूप दीजिए। गांव को एक युनिट के रूप में मानिये। पशुओं का भी बीमा करने की आवश्यकता है। आप कारों, ट्रकों और बसों का तो बीमा करते हैं, लेकिन किसान के लिए तो ट्रक, बस या कार पशु ही हैं। किसान की सारी खेती पशुधन पर निर्भर करती है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे देश में पशुओं की संख्या अधिक होते हुए भी दूध की कमी है और पशुओं का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है। इसका कारण यह है कि हम खली विदेशों में भेज देते हैं। खली का निर्यात कर दिया जाता है। इसी प्रकार की स्थिति चोकर की भी है। वह भी ऐवेलेबल नहीं होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस तरफ भी ध्यान दीजिए।

इसके साथ-साथ जो ऊसर जमीन है, जहां पर रेगिस्तान हैं उनकी तरफ भी ध्यान देने की जरुरत है। गांवों के आसपास जो ऊसर भूमि है वह गांवों में भूमिहीन लोगों और खेतीहर मजदूरों में मुफ्त में बांट दी जानी चाहिए जिससे वे लोग अपने जीवन का निर्वाह कर सकें। वृक्षों के लगाने पर भी आप जोर दे रहे हैं। वृक्षों के रख-रखाव पर भी आपको स्वयं व्यय करना चाहिए।

आखिरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आजादी के इन 40 वर्षों के बाद भी हम सिर्फ 30 प्रतिशत भूमि को ही सिंचित कर पाये हैं। 70 प्रतिशत भूमि अभी भी सिंचाई से वंचित है। इसलिए हमारी योजनायें 70 प्रतिशत असिंचित जमीन की ओर ध्यान रखते हुए बनाई जानी चाहिए। जहां पर नहरें हैं उनका पानी 45 प्रतिशत नष्ट हो जाता है। यही हाल गूलों का भी है। इसलिए पानी को नष्ट होने से बचाने के लिए नहरों और गूलों को पक्का किया जाना चाहिए। जो सुझाव मैंने दिये हैं, अगर हम उन पर अमल करेंगे तो हमारे देश का किसान भी खुशहाल होगा और देश भी खुशहाल होगा।

PAPERS LAID QN THE TABLE—Contd
Notifications of the Ministry of Finance (Department of Revenue)

, THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EXPENDITURE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI B. K. GADHVI): Madam Deputy Chairman, I beg to lay on the Table, under section 159 of the Customs Act, 1962, a copy each, (in English and Hindi) of thai following Notifications of the Ministry of Finance (Department of Revenue), together with an Explanatory Memorandum thereon:—

(i) No. 152/88-Customs, dated the 2nd May, 1988, amending Notifications Nos. 224/81 Customs, dated the 1st October, 1981 and 136/86-Customs, dated the 17th February, 1986, so as to (a) reduce basic customs duty on Vinyl Chloride Monomer imported for manufacture of PVC from existing 10 per cent *ad valorem* to 5 per cent *ad valorem,* and (b) reduce basic customs duty on Mono Ethylene Glycol from the existing 110 per cent *ad valorem* to 45 per cent *ad valorem.*

(ii) No. 153/88-Customs, dated the 2nd May, 1988, exempting auxiliary duty on Vinyl Chloride Monomer imported for manufacture of PVC. [Placed in Library. *See* No. LT-6043A /88 for (i) and (ii)]

DISCUSSION ON THE WORKING OF THE MINISTRY OF AGRICULTURE... contd.

श्री राम चन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदया, . . . (व्यवधान) . . सदन कब तक चलेगा ?

[The Vice-Chainnan (Shri Anand Sharma in he Chair)

श्री मीर्जा इर्शादबेग : मैं आपको बधाई देता हूं जो पहली बार आपने यह आसन ग्रहण किया।

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: Mr. Vice-Charman, I congratulate you on the occasion of your taking the Chair.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondi-cherry) I also congratulate you, Mr. Vice-Chairman on your occupying the Chair.

श्री राम चन्द्र विकल : उपसभाध्यक्ष महोदय, सारा सदन जब आपको बधाई देना चाहता है तो मुझे और ज्यादा देनी चाहिए क्योंकि पहला वक्ता मैं ही हूं जबकि आपने यह आसन पहली बार ग्रहण किया ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, किसानों की समस्या पर जिस गंभीरता से यहां पर चिंतन हो रहा है उस पर अपने विचार प्रकट करने के लिए मुझे भी बोलने का अवसर दिया गया है। महोदय, यह सच है कि किसानों की समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है और इसलिए इसका निराकरण भी राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पर ही इस समस्या के बारे में सोचा जाना चाहिए। उपसभाध्यक्ष महोदय, किसान को इस देश का अन्नदाता कहा जाता है। लेकिन मैं गांवों में भी पूछता हूं और यहां, इस सदन के माध्यम से भी मैं पूछना चाहता हूं कि किसान केवल अन्नदाता ही क्यों है ? यह बतलाइये कि वस्त्रदाता कौन है, दूध दाता कौन है, फल दाता कौन है, सब्जी दाता कौन है, मक्खन दाता कौन है, मलाई दाता कौन है, गोश्त दाता कौन है, चमड़ा दाता कौन है । मसाला दाता कौन है सर्वदाता उसको कहना चाहिए । सब कुछ यही देता है। महोदय, वेदों और शास्त्रों ने माना है कि अन्न ही प्राण हैं, अन्न में प्राण बसते हैं। यह हमारे शास्त्र और वेद मानते हैं। तो किसान को प्राणदाता क्यों नहीं माना जाता है .... (**व्यवधान**) ... बिना अन्न के रहे होंगे ऐसे तो कम लोग हैं और वे किसी न किसी और वस्तु के द्वारा जीवित रहे होंगे । केवल हवा खाकर जीने वाले लोग, मेरी समझ में नहीं आता कि केवल हवा पर लोग जीवित रहते होंगे ।

खैर, मैं यह कह रहा था कि वह प्राणदाता भी है और सब कुछ देने वाला वही है । डाइरेक्ट और इनडाइरैक्ट टैक्स की बात भी आप लें तो वह किसी से कम नहीं है । यह टैक्स भी किसान को देना पड़ता है। लेकिन वह भिखारी क्यों है इसका मेरे मन में एक संताप है । आप उसको भिखारी मान सकते हैं और बाप भी भाव के लिए । सभी लोग चर्चा करते हैं और अभी हमारे श्यामलाल यादव जी ने चर्चा की कि कृषि लागत मूल्य आयोग की । यह चर्चा पिछले चार-पांच साल से मैं सुन रहा हूं । लेकिन इस आयोग का गठन किया गया है या नहीं इसका कृषि मंत्री जी आप जवाब दें ।

श्री कल्पनाथ राय : नहीं है ।

श्री भजन लाल : है ।

श्री राम चन्द्र विकल : है तो उसका नाम बताइये । मैं यह जानना चाहता हूं ।

श्री भजन लाल : आपको बताउंगा।

श्री राम चन्द्र विकल : मुझे बोलने दीजिए मुझे अंत में समय दिया गया है ।

श्री भजन लाल : आप आराम से बोलें । कल आराम से जवाब दे दूंगा।

श्री राम चन्द्र विकल : मैं यह जानना चाहता हूं कि कृषि लागत मूल्य आयोग की घोषणा कब की गई थी और उसका गठन कब किया गया, उसके सदस्य कौन-कौन हैं और उसने किसानों की किन चीजों के मूल्य का फैसला किया है । अधिकारियों के बारे में मैं जानता हूं । अधिकारी तो करते ही रहते हैं। कृषि लागत मूल्य आयोग में अधिकारी भी होंगे और वे हों न हों वे तो पालिसी मेकर हैं ही, वे मानते हैं लेकिन किसानों के लिए बूटासिंह जी ने, जब वह कृषि मंत्री थे, जिस कृषि लागत मूल्य आयोग की घोषणा की थी उसका गठन कब हुआ है और उसने कब से काम करना शुरू किया यह मेरा पहला प्रश्न है ।

दूसरा, मैं यह जानना चाहूंगा श्यामलाल यादव जी अगर न बोलते तो मेरा भाषण कुछ और तरह का होता, मेरे विचार भी कुछ और होते। लेकिन उनका सुनकर मेरे विचार बदल गये। उन्होंने कहा कि कृषि उद्योगों की समता नहीं कर सकती। ऐसा सुनकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उद्योगों से उसकी समता क्यों न की जाय, कृषि को उद्योग क्यों न माना जाय? उद्योगों के ऋण की दर क्या है, उसकी बिजली की दरें क्या हैं, उद्योगों को दिये हुए साधन क्या हैं किसानों के मुकाबले में? इसलिए हम चाहते हैं कि कृषि को उद्योग माना जाय। अनेक रियायतें उद्योगपतियों को हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उद्योगपति जो पैदा करते हैं उसकी कीमत अपने आप मनमाने ढंग से नियत करते हैं और किसान जो पैदा करता है उसको मनमाना मूल्य नहीं मिलता है। यह फर्क है उद्योग और कृषि में। दूसरा फर्क यह है कि जो उद्योगपति है चाहे पनवाड़ी ही क्यों न हो चाहे छोटा दस्तकार हो, चाहे कोई मजदूर हो कोई भी बिना पैसे लिये काम पर नहीं जाता है न अपनी कोई चीज बिना पैसे लिए देता है लेकिन किसान ऐसा अभागा है जिसका गन्ना तो ले लिया जाएगा कई वर्ष तक उसका मूल्य उसको नहीं दिया जाता है न उसको कोई सूद का भुगतान किया जाता है बावजूद इसके कि उसको सूद भी दिया जाना चाहिए। किसान एक ऐसा है जिसके साथ ऐसा व्यवहार होता है इसलिए मैं मांग करता हूं कि उद्योगपतियों की तरह से किसान आप ट्रीट करो उसकी देखभाल करो और जैसे उद्योगपतियों की रियायतें दी हैं वैसे किसानों को भी दो। यह फर्क है। क्या कारण हैं कि कृषि को आप उद्योग नहीं मानते? कृषि मूल्य इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि हम विदेशों से कब क्या चीज मंगाते हैं। प्रायः यह देखा जाता है कि देश की एकता के लिए बड़ा जरूरी है जैसे आजकल अकाल पड़ा हुआ है देश के काफी हिस्सों में काफी कम पैदावार हुई है लेकिन दुर्भाग्य यह है कि यह जो पैदावार हुई है उसको देश के हर हिस्से में जाने की इजाजत नहीं है इससे दो फायदे होते हैं। उत्पादक को पैसा ज्यादा मिलता है और उपभोक्ता को सस्ती चीज मिलती है लेकिन यह नीति मेरी समझ से बाहर है कि उधर उपभोक्ता परेशान है। महंगी चीज खरीद कर जो उत्पादक है उसको उसका उचित मूल्य भी नहीं मिल रहा है। इससे उन लोगों को फायदा हो रहा है जो बिचौलिये हैं जो किसानों से सस्ते दामों पर ले लेंगे और बाद में महंगे दामों पर बेचेंगे। हमें अकाल पीड़ितों के साथ भी हमदर्दी है इसी तरह से समाज की व्यापारियों की अधिकारियों की कर्मचारियों की सब की हमदर्दी उनके साथ होनी चाहिए। मैं कई जगह सूखा राहत क्षेत्रों में गया हूं मैंने यह देखा है कि लोगों में मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति है चाहे अधिकारी हों, कर्मचारी हो चाहे और दूसरे काम करने वाले हों उन में सहानुभूति नहीं है। गरीब आदमी परेशान है और व्यापारी अधिक से अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं। अगर बीमार हो जाएं तो डाक्टर की फीस भी बढ़ जाएगी। अकाल के कारण व्यापारियों के दाम बढ़ जायेंगे। मैं य कहना चाहता हूं कि यह मजबूरी से मुनाफा कमाने की जो मनोवृत्ति है यह हमारे देश को खाए जा रही है और यह प्रवृत्ति बढ़ रही है। यह देश के लिए बहुत जरूरी है कि जो चीज देश में पैदा हो उसको देश के हर हिस्से में जाने आने दिया जाना चाहिए उससे उपभोक्ता और उत्पादक दोनों को लाभ होगा। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप यह लाभ उनको क्यों नहीं देना चाहते हैं। यह बिचौलिये और विदेशों से मंगाने वाली नीतियां ऐसी हैं जो किसान को पसीने बहाने के बावजूद मालदार नहीं बनने देना चाहते हैं। यदि हम बाहर से अनाज मंगाते हैं तो किसान की पैदावार के दाम कम हो जाएंगे। ठीक है हमारे देश में इतना संकट है पैदावार नहीं है तो उसको बाहर से मंगाना चाहिये लेकिन सब से पहले प्राथमिकता किसान को उत्पादक को पैदावार करने वाले को देनी

[श्री रामचन्द्र विकल]

भाव से हम विदेशों से मंगाते हैं गल्ला मंगाते हैं जैसे अभी हम 10 लाख टन गल्ला मंगा रहे हैं तो मेरा कहना यह है कि जिस भाव से हम बाहर से गला मंगा रहे हैं कम से कम वह भाव हमारे यहां के किसानों को अवश्य दिया जाना चाहिये। इस तरह से हमारा किसान प्रोत्साहित हो कर के उतना अधिक उत्पादन यहां कर सकता है बढ़ा सकता है। हम विदेशों को देंगे, व्यापारियों को देंगे लेकिन उत्पादक जो यहां का है उसको यह भाव न मिल पाए यह किसान के हित में आपकी नीति नहीं जा रही है। हमारे देश का स्वाभिमान खरीदा जाता है उस वक्त जब हम विदेशों से अन्न मंगाते हैं हम भीख मांगते हैं। मुझे याद है 1965 में इंदिरा जी जो अब स्वर्ग में हैं अमरीका गई थीं और जब उन्होंने वहां से अन्न मांगा तो उन्होंने तरह-तरह की शर्तें लगा दी थी जिससे हमारे स्वाभिमान को ठेस लगती है। लेकिन इंदिरा जी ने कहा कि हम अन्न के अभाव में अपने देश के स्वाभिमान को नहीं बेचेंगे। इससे तो यह होगा कि मैं अपने देश के किसानों और मजदूरों से अपील करूंगा कि वे आधा पेट रहने दें और अपने देश में उत्पादन बढ़ाएं परन्तु देश का स्वाभिमान बेच कर मैं नहीं जाऊंगी। वे खुल कर कहा करती थीं कि देश का स्वाभिमान देश के अन्दर पैदावार बढ़ाने से है न कि विदेशों से सामान मंगा कर है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि यह तो किसानों का हौसला पस्त करने वाली बात है। यह किसान को कम दाम देने वाली नीतियां है चाहे चीनी मंगाई जाए या गल्ला मंगाइये। कुछ किसानों के बारे में कह रहा था। मैं यहां यह भी कह देना चाहता हूं कि आवश्यकता पड़ने पर बाहर से चीज मंगानी पड़े तो मुझे उस में एतराज नहीं है। जहां तक खाद का प्रश्न है इस में सबसीडी तो किसान के नाम पर दी जाती है लेकिन ज्यादातर फायदा मिलता है खाद पैदा करने वालों को। सब्सिडी किसान के नाम पर और फायदा उठा रहे हैं उद्योगपति। उसे बिजली की सस्ती दर दी जायेगी, उसे कोटा और परमिट दिये जायें और नाम किसान का लगेगा। बड़ी होशियारी से किसान को मारा जा रहा है। बड़ी बुद्धिमत्ता से किसान को मारा जा रहा है; हर क्षेत्र में किसान को मारा जा रहा है और उस उत्पादक के हौसले को बढ़ाने की कोशिश नहीं की जाती है। सब्सिडी किसान के नाम पर और पा रहे हैं कुछ और लोग और उपसभाध्यक्ष महोदय इसमें से बीच में कितना बंट जाता है। उस तक पहुंचते पहुंचते ऐसा हाल हो जाता है जैसे टेल पर नहर के पानी का हो जाता है। ऊपर से काट कूट कर किसान को मिलता है। टेल पर पानी की जो हालत पर वही किसान की सब्सिडी में, सहायता में, लोन में और कर्जे आदि सबमें हैं, चाहे बैंक ही हो बीच में बिचौलिये बैठे हुए हैं। बेचारे बेपढ़े किसान को न बैंक वाले सही ढंग से दे पाते हैं न उसे सरकारी सहायता सही मिल पाती है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं कि कौन-कौन बीच में भागीदार हो जाते हैं। उसको कम से कम प्राप्ति होती है।

उपसभाध्यक्ष (श्री आनन्द शर्मा) : आप दो मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री राम चन्द्र विकल : मुझे तो वर्मा जी के बराबर भी समय नहीं मिला।

उपसभाध्यक्ष (श्री आनन्द शर्मा) : हर पार्टी के लिए समय पहले से तय किया गया है।

श्री राम चन्द्र विकल : इस समय के बारे में मेरा एक और निवेदन है कि मंत्रियों का समय भी सामूहिक होना चाहिए, सारे सदन का होना चाहिए हमारी पार्टी में से नहीं कटना चाहिए। जवाब तो इनसे लें और ज्यादा समय हमारा लें। इनका सारा समय सामूहिक होना चाहिए मंत्री सारी सरकार के होते हैं न कि पक्ष के इसलिए इनका समय हमारे में नहीं लगना चाहिए।

श्री भजन लाल : ज्यादा उनकी तरफ का जवाब देना पड़ता है ।

श्री राम चन्द्र विकल : इसलिए इनका समय ज्यादा उनकी तरफ जाना चाहिए . . . (**व्यवधान**) . . . तुम्हारी अच्छी बातों को मानता हूं . . . (**व्यवधान**) . . . देखिए जो पक्ष विपक्ष की अच्छी बातें हों मैं उनको मानता हूं लेकिन जो खराब बात है वह तुम्हारी भी खराब हमारी भी खराब है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री आनन्द शर्मा) : विकल जी, आपको कांग्रेस पार्टी के जो सदस्य हैं उनसे 5 मिनट ज्यादा समय दिया जायेगा ।

श्री राम चन्द्र विकल : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा था कि किसान जो अन्न पैदा करते हैं यह एटम बम से बड़ी शक्ति रखता है । इसलिए उसका महत्व ज्यादा होना चाहिए । हीरोशीमा और नागासाकी में दूसरे विश्व युद्ध के समय एटम बम गिराये गये लेकिन वहां 35 लाख आदमी नहीं मरे लेकिन बंगाल और बंगलादेश में दूसरे विश्व-युद्ध के पहले अन्न के अभाव में 35 लाख लोग मर गये थे ।

श्री वीरेंद्र वर्मा : 42 लाख लोग ।

श्री राम चन्द्र विकल : मुझे तो 35 लाख के आंकड़े मालूम हैं । वीरेन्द्र वर्मा के पास ज्यादा हैं । चलो इन्होंने कुछ और बढ़ा दिया । मैं 35 लाख मानता हूं लेकिन 42 लाख लोग अन्न के अभाव में चले गये । युद्ध से इतना खतरा नहीं है, युद्ध से इतनी जानें नहीं गयीं, एटमबम से इतनी जानें नहीं गयीं जितनी अन्न के अभाव से चली गयीं । लिहाजा अन्नदाता को आदर भी दो और साधन भी दो । जिस तरह से सत्ता और सम्पत्ति को सम्मान मिला है उस तरह से श्रम और सेवा को नहीं मिला है । यदि श्रम और सेवा को सम्मान दें दें तो समाजवाद नाम की व्याख्या पूरी हो सकती है । समाजवाद का नारा मात्र जब तक है, जब तक श्रम और सेवा को वैसे ही सम्मान नहीं मिलेगा जैसा सत्ता और सम्पत्ति को मिलता है तब तक समाजवाद नहीं आयेगा । श्रम और सेवा को सम्मान देना ही पड़ेगा अगर देश की आर्थिक क्रांति करना चाहते हैं । गरीब मेहनतकश को बढ़ावा देना चाहते हैं, पसीना बहाने वाले के आंसू नहीं बहने देना चाहते हैं तो श्रम और सेवा दोनों को सम्मान और साधन देने चाहिए खाली सम्मान से काम नहीं चलेगा । साधन भी उनको ही देने चाहिए जो श्रम करते हैं जो मेहनत करते हैं जो सेवा करते हैं ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि भूमि अधिग्रहण कानून किसानों के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है इस वक्त देश में, कहीं भी आप आंकड़े ले लें, मुआवजा उसके मुताबिक नहीं मिल रहा है, उसकी मर्जी से जमीन नहीं ली जाती है, नोटिस उसको नहीं होती है, कब तक जमीन एक्वायर होनी है कोई पता नहीं है । दिल्ली और बड़े शहरों के आस-पास अधिग्रहण को अगर देखें तो यहां किसानों को अपार कष्ट और इसका कोई जवाब नहीं है तथा अधिकारी मालामाल हो रहे हैं किसानों की जमीन बेच कर । अधिकारी व्यापार भी कर रहा है, पोलिटिक्स भी कर रहा है और नौकरी भी कर रहा है, तीनों काम कर रहा है और किसानों मारा जा रहा है अकेला बेचारा । उसकी जमीन का मुआवजा उसकी मर्जी से तय नहीं होता है, दिया नहीं जाता है उसकी मर्जी से और बहुत कम दिया जाता है और उसको लेने के बाद जो दाम बढ़ते हैं तो वे आसमान को छू जाते हैं चाहे दिल्ली की जमीन हो या यू० पी० की, शहर कोई भी हो चाहे बम्बई हो या कलकत्ता, शहरों के नजदीक जो जमीन ली जा रही है उसमें मुफ्ती तौर पर किसानों को जिबह और परेशान किया जा रहा है । उनकी मदद नहीं होती है । उनकी जमीन बिना मुआवजा दिये नहीं लेनी चाहिए और सरकारी कामों के लिए राष्ट्रीय कामों के लिए, ली जाये तो

[श्री रामचन्द्र विकल]

कोई हर्ज नहीं है लेकिन आज चाहे जिसको आबाद करने के लिए बसाने के लिए एक तरफ से किसानों के साथ बड़ा भारी अन्याय किया जा रहा है। मैं एक-दो बातें और कहना चाहूंगा। सूखा और देवी आपदाएं जितनी भी हैं किसान उनका सब से बड़ा भुक्तभोगी है। चाहे अतिवर्षा हो, चाहे सूखा हो, चाहे ओला पड़ जाए, चाहे मवेशियों में बीमारी आ जाए या फसलों में बीमारी आ जाए जो भी बीमारी है उस सब का असर किसान पर पड़ता है। वह पांच वर्ष की सीमा थी अब तो वह सीमा लांघ गए कि पांच वर्ष में दुष्काल कहीं न कहीं आ जाता है। अब 15 राज्यों में 3-4 वर्ष से अकाल पड़ा हुआ है। उसके बीमा की चर्चा वर्मा जी ने भी की और मैं भी जानना चाहता हूं कि ऐसी मुसिबत के वक्त में फसल बीमा, मवेशी बीमा उसके लिए कहीं पर है या नहीं है और है तो किस रूप में है। उसकी रूप रेखा होनी चाहिये। उसको इस वक्त कहीं कुछ सहायता नहीं दी गई है 15 राज्यों में जो कि सूखे वाले है और बाढ़ वाले हैं, आप बता दें ? मवेशियों की बीमारी से जो हानि हुई है कितने मवेशी जो छोड़कर चले गए तिलक लगा लगा कर, मुझे मालूम। मैं पिछले दिनों जैसलमेर गया था, एक साल पहले की बात है। किसान मवेशियों को अपने सामने मरता हुआ, नहीं देख सकता क्योंकि उसकी सबसे बड़ी सम्पत्ति मवेशी होते हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, मनुष्य के लिए तो बैठकर रोते हैं लेकिन मवेशी मर जाए तो खड़े हो कर रोते हैं। इतना भारी उसका मोह होता है। मवेशी उसका सहायक भी होता है। तिलक लगा-लगा कर उसे सड़कों पर छोड़ जाते हैं। उसके लिए बीमा की शक्ल में कुछ दिया गया है ? चाहे राज्य सरकार ने दिया हो, चाहे केन्द्रीय सरकार ने दिया हो, किसी की तरफ से कोई सहायता इस दुष्काल में हो सकी है या नहीं हो सकी इसकी जांच होनी चाहिए मंत्री जी आपके द्वारा और मुझे मालूम है आप गुजरात में गए थे जब आप पर्यावरण मंत्री थे। आपने दौरा भी किया, क्योंकि मैं जाता रहता हूं सारे देश में घूम कर हालत मालूम करता हूं। आज फिर दोबारा आप जाएं उन्हीं राज्यों में जहां किन्सूखा है।

श्री भजनलाल : अभी जाकर आया हूं।

श्री राम चन्द्र विकल : हां, जरूर मौके पर जाकर देखें। मेरी रिपोर्ट अगर गलत है तो बता दें। सही सहायता सही जगह नहीं पहुंच रही है। इसकी आप जांच करें। किसी भी राज्य में जाकर देखें। मैं भी गया हूं और जाता रहता हूं और सही सहायता केन्द्रीय सरकार की राज्य सरकारों की इस मुसीबत के वक्त में भी नहीं जा रही है तो कब जायेगी। उसकी चैकिंग सख्त से सख्त होनी चाहिए। जो भी दोषी हो, चाहे कोई अधिकारी हो या कोई और हो या चाहे फिर पब्लिकमैन हो उनके लिए दंड व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसी मुसीबत के वक्त में जो मदद को धोखे में डालता है या अपने आप खा जाता है उससे बड़ा महापाप और कोई नहीं हो सकता है। इसकी जांच होनी चाहिए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। वर्मा जी कह रहे थे, बीज सस्ता दिया जाए मैं भी मांग कर रहा हूं और मैं बीज फार्म का चेयरमैन रहा हूं डढ़ साल और मैंने फार्म बढ़वाए। आप कोई राज्य बता दो जहां से फार्म खोलने के लिए मेरे सामने मांग न आई हो। देश का ऐसा छोटा या बड़ा कोई राज्य नहीं है जहां से ऐसी मांग नहीं आई हो। हरेक का कहना था कि हम जमीन देने को तैयार है और आप हमारे यहां फार्म खोलो। मध्य प्रदेश में बंवई और शहडोल फार्म की मांग आई। बवई के फाम पर मैं गया और ले लिया आज वह लौटा दिया गया। राज्य सरकार का, चीफ सेक्रेटरी का और चीफ मिनिस्टर का चिट्ठी मौजूद है रिकार्ड में कि हमारे यहां फार्म खोलो। आज फार्म बंद किए

जा रहे हैं। अनेक फार्म बंद कर दिए गए। नए फार्म लिए नहीं गए तो बीज कहां से आयेगा। फार्म तो आप बंद कर रहे हैं आप किसानों को बीज कहां से देंगे? किसान को सरकारी फार्म से बीज नहीं मिल रहा है।

श्री कल्पनाथ राय: बंद क्यों कर रहे हैं?

श्री राम चन्द्र विकल: अब यह तो भजन लाल जी बतायेंगे या फिर श्याम लाल यादव जी बतायेंगे। दोनों संबंधित हैं। मैं अभी नहीं बताना चाहता।

श्री भजन लाल: आप तो चेयरमैन हैं।

श्री राम चन्द्र विकल: जी हां, मैंने बढ़ाए। अगर विदेश से भी मेरे सामने मांग आई कि एक्सपर्ट्स दो, बीज दो तो हमने भेजे भी और दो साल के कारनामें बताता हूं और घाटे वाले फार्म हमने मुनाफे में कर दिए। यह फार्म हाउस मेरा ही बनाया हुआ है, श्याम लाल जी, तुम तो मौके पर गए थे। इंजीनियर लोग तो यह कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं हैं। यह तो फंड देने वाली चीज है। अब ढाई लाख तो किराया आता है, एक-तिहाई किराए पर है और दो-तिहाई में दफ्तर चलता है और मुनाफा सोचा जाता है तो मुनाफा कैसे हो? आप तो पेड़ बेचकर मुनाफा दिखा रहे हो। पेड़ों को निकाल कर जो कि सकड़ों साल से खड़े हैं। सूरतगढ़ आदि फार्मों पर पेड़ बेच कर मुनाफे में जोड़ दिए। पैदावार कितनी बढ़ रही है? हमने दो साल में घाटे के फार्म मुनाफे में ला दिए इसलिए कि वहां जाकर दिलचस्पी ली, अधिकारियों का सहयोग लिया, छोटे कर्मचारियों का सहयोग लिया और जो घाटे के कारण मवेशी थे एक-एक फार्म में उसके मवेशी निकलवा दिए जिन्हें कि वह लोग कहते थे कि पुलिस से कई बार डंडे मार-मार कर निकाले, लेकिन हमने बिना पुलिस के सारे फार्मों से मवेशी निकलवाये। मैं नहीं कहना चाहता। व्यक्तिगत रुचि लेने से विभागों में सुधार होते हैं और फिर उसमें सुधार ही नहीं, मुनाफे होते हैं। घाटे के काम का मैं कभी हामी नहीं रहा। हम जब बीज अपना महंगा बेचते हैं तो घाटे का सवाल क्यों आता है? मैं अधिक समय न लेते हुए आपका धन्यवाद करता हूं और कृषि मंत्री जी से विशेषकर यह चाहूंगा कि हमारा किसान इतना उपयोगी है कि वह सेनाओं के जवान भी देता है, उनकी ओर ध्यान देना चाहिए।

उपसभापति महोदय, शास्त्री जी का यह नारा था--"जय-जवान जय-किसान"। यह दोनों चीजें एक में ही निहित हैं और वह किसान में। जवान की आंख किसान का अन्न खाकर खुलती है, सारी दुनियां की आंख किसान का अन्न खाकर खुलती है, चाहे वे अधिकारी हों या कर्मचारी हों या व्यापारी हों या मजदूर हों और मजदूर तो भागीदार है किसान का, मजदूर एक तरह से खेती में उतना ही हकदार है, जितना कि किसान। इसलिए किसान और मजदूर की तरफ आंख खोलकर देखो, उनकी समस्याओं को देखो और उनका समाधान करो तभी देश की आर्थिक क्रांति हो जाएगी, सामाजिक क्रांति हो जाएगी और हमारा देश उत्थान की तरफ चला जाएगा।

इन्हीं शब्दों के साथ में फिर आपका धन्यवाद करता हूं।

SHRI N. E. BALARAM: Mr; Vice-Chairman, Sir, except the hon. Minister, Shri Yadav, who intervened in the debate a couple of minutes back, I think nobody has contested the fact that our agriculture is facing a very serious crisis. He has tried to draw a rosy picture about agriculture. I am sorry, Sir, I do not agree with that. Perhaps, he might not have the time to read the Mid-term appraisal of the Plan about our agriculture. In the Mid-term appraisal of the Planning Commission, in regard to agriculture, they said that our agriculture is facing a crisis for the last three years due to a shortfall in production. The entire country must be

[Shri N. E. Balaram] very careful and unless immediate steps are taken, the situation will become worse. This is the opinion expressed in the Midterm appraisal by the Planning Commission about our agriculture I do not know whether our hon. Minister agrees with that or not. He may disagree with, that. But this is the mid-term appraisal which. I have read in the report. Anyway, I feel that agricultural economy is in a bad shape. We are now slowly moving towards importing a large amount of food, for importing a large amount of raw materials for our industry. T think, this is a very bad situation. In a country like India where 70 to 80'per cent of the population consists of agriculturists, in such a country, if we are going to import food items and if we are going to import raw materials for our industry, I think, the situation is very serious, according to me. It is in the press that the Government of India is trying to import about one million tonnes of wheat from the United States. About 75,000 tonnes of rice has already been coming from Burma to India. Sir, I recall the days of PL-480 when our country was importing a large amount of wheat and rice from abroad...

SHRI V. NARAYANASAMY: Those days have gone.

SHRI N. E. BALARAM: K those days are gone, I am very happy. One cannot be sure. Of late, by open general licence, the Government have allowed the import of a variety of items which are very much essential as industrial raw materials like, rubber, copra, coco, a large number of items, they have decided to import. If this is the position, bow can one say that our agricultural economy is improving? This was not the case before the last three or four years. Of course one can agree that partly the reason for the fall of production is drought. I do) not disagree with that. This is a fact. But I do not agree that drought alone is the 'reason for the fall in production. According to me the Government policies have also contributed to the fall in production and to the state pf affairs of the agricultural economy at the present moment.Our agricultural production was stagnating for the last three years around 150 million tonnes. We are talking much, about self sufficiency. I do not. disagree with that. But if we take the total per capita consumption, in spite of the growth in grain production there was no perceptible expansion in per capita consumption, it had remained invariably unchanged at about 185 kgs for the last 30 years, from 1954 to 1984. Invariably it was remaining around 185 kgs. How can you say that our country is- self-sufficient if this is the real picture? This is not a statistics calculated by me. All the agricultural economists' whether they are rightists or leftists or Marxists all of them are agreed on this point. In spite of the green revolution the benefit has not gone down to the grassroot level *to* the masses. There food consumption rate is very low even now. So, this so-called self-sufficiency is a myth according to me, as far as the common man is concerned. , It is not a fact. I do not say that there are starvation deaths. I do not go to that extent. Of course there were reports during the period of drought in some areas but we cannot say that there were widespread starvation deaths. I do not say that. But we should not be proud of saying that since we are able to produce 150 million tonnes of rice or grains, since our country has become self-sufficient, the consumption rate of average common man has risen. According to me that is not a fact. .That is what I am driving at.

Now, the second point I want to put forward is that we have got a number of anti-poverty - programmes. It- also comes under the Agriculture Ministry. It is a good programme. Many of the programmes are very good. They have got a number of programmes. But we must understand that this year, I think the agricultural production will come down by about 20 million tonnes. That is what the general consensus among the agricultural economists is and I think that the Planning Commission is also more or less agreed on that opinion. If I remember well, last year the total production was 148 million tonnes. If a decline of 20 million tonnes takes place....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ANAND SHARMA): You have to conclude in two minutes.

SHRI N. E. BALARAM: Then I have have nothing to say.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ANAND SHARMA): The time allotted to you is already over. But you can take two or three minutes more.

SHRI N. E. BALARAM: What 1 am saying is that there is *A* decline of 13 per cent in the grain production this year. It has been estimated by the Planning Commission that on an average, for a decline in agricultural output by 10 per cent, there will be a cut-back in employment of labour to the extent of 6 per cent. On this basis, it has been estimated by the Planning Commission that people below poverty line in the country would be losing as many as 1400 million man days of employment this year on account of drought. *As* against this, according to the anti-poverty programmes we have provided only for 500 million matt-days work, and because of this 10 per cent decline in production, I don't know what will happen to the other 900 million man-days' work. What will happen to that much amount of unemployment in the rural areas if you go according to the present scheme? Decline! in production will naturally affect agricultural workers, poor peasants, and there will be unemployment in the villages affected by .the decline in production. I know, you have got programmes; you have selected about 190 districts and you already have programmes. I agree. But if you want to implement those programmes, it will depend upon other factors as well. Firstly, it is irrigation. If there is no proper irrigation, we cannot have the programmes implemented. On the question of irrigation, there are about 500 major and medium irrigation schemes at various stages of development in the country.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ANAND SHARMA): You will have to conclude now.

SHRI N. E. BALARAM: All right; I conclude now. Thank you.

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, सदन में कृषि नीति पर बहस हो रही है। मैं सर्वप्रथम कृषि मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद वे किसानों के हित में कुछ ठोस और समयबद्ध कदम उठा रहे हैं।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, देश के नेता और भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश को जय जवान, जय किसान का नारा दिया। हिन्दुस्तान की बुनियादी चिन्तन की पकड़ लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा हुई। भारत जो गांवों में रहता है, उसके विकास का ध्यान रखा। महोदय, यूरोप का विकास इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण हुआ यानी शहरीकरण और औद्योगीकरण के माध्यम से यूरोप का विकास हुआ इंडस्ट्रियल रेवलूशन के बाद। हिन्दुस्तान का विकास. हिन्दुस्तान की कृषि, हिन्दुस्तान के गांव और गांवों में रहने वाले किसानों और मजदूरों के माध्यम से होगा। जब तक यह बुनियादी चिन्तन हमारे नेताओं और हमारे कृषि मंत्रालय के मन में नहीं आएगा, अपने देश का हम विकास नहीं कर सकते।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे देश का विकास अनाज के उत्पादन से, फलों के उत्पादन से, दूध के उत्पादन से, इन तीनों चीजों के साइमल्टेनियस उत्पादन से होगा। तभी यह मुल्क मजबूत होगा। 80 करोड़ जनसंख्या को अनाज तो हम दे रहे हैं मगर क्या उनको फल हम दे रहे हैं, क्या हम उनको दूध दे रहे हैं और क्या बिना दूध के एक मजबूत किसान या मजबूत जवान पैदा होगा? हिन्दुस्तान का किसान अपना खून-पसीना एक करके, खेतों में हल चलाकर हिन्दुस्तान का उत्पादन बढ़ाता है दूसरी तरफ उसी का बेटा 15–15 हजार फीट ऊंचाइयों पर, बर्फ की चट्टानों पर खड़ा होकर मातृभूमि की रक्षा करता है लेकिन उस किसान की हालत, मेरी दृष्टि में किसान के संबंध में जो नीति अपनानी चाहिये वह नहीं हो रही है। हमारे देश में पंडित जवाहर लाल नेहरू की नीति के परिणामस्वरूप देश का उत्पादन बढ़ा है। 150 मिलियन

[श्री कल्पनाथ राय]

टन आज हिंदुस्तान का एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है लेकिन चीन का प्रोडक्शन 400 मिलियन टन है। एशिया के दो बड़े देश हैं—एक हिमालय के इस पार, एक हिमालय के उस पार। चीन का उत्पादन आज 400 मिलियन टन है और हिंदुस्तान का 150 मिलियन टन है। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये जब हम कोई प्रगति का लेखा-जोखा करें तो हम अपने सामने चीन की तस्वीर को रखें क्योंकि यही एशिया के दो बड़े देश हैं जिनकी तुलनात्मक शक्ति के आधार पर हम अपना संश्लेषण और विश्लेषण कर सकते हैं। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, हिंदुस्तान में पर-कॅपिटा, पर-हैक्टेयर उत्पादन सबसे कम है। पर-हैक्टेयर फर्टिलाइजर का कंजम्पशन भी कम है। हिंदुस्तान में जो हमारी पंचवर्षीय योजनायें, जो हमारी राष्ट्रीय आमदनी थी वह भी घट कर 62 परसेंट से 30 परसेंट हो गयी है।

आदरणीय वर्मा जी ने जो बातें कहीं, आदरणीय रामचन्द्र विकल जी ने जो बातें कहीं, हमारे मित्र यादव जी ने जो बातें कहीं, उन बातों से हम सहमत हैं। मुझे एक बात कहनी है कि जब तक हिंदुस्तान के अंदर एक दाम बांधो नीति, प्राइस पैरिटी निर्धारित नहीं की जाती, तब तक हिंदुस्तान के किसानों का, गांवों का, खेती का विकास नहीं हो सकता। गांवों में कौन रहता है, जो गरीब होगा। गरीब कौन है, जो खेती करेगा। महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज्य, ग्राम स्वावलम्बन, खेती का विकास, जो आजादी की लड़ाई का सबसे बड़ा उद्देश्य था, आज वह खत्म हो रहा है। लोग भारी संख्या में गांवों को छोड़ कर भाग रहे हैं। शहरों की तरफ। दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जहां लोग शहरों को छोड़ कर गांवों में जा रहे हैं पर हिन्दुस्तान में ठीक उल्टा है। बड़ा ही भारी माइग्रेशन है, अरबन एक्सप्लोजन है, पब्लिक गांवों को छोड़ कर भाग रही है क्योंकि जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिये गांवों के लोगों को वह नहीं मिल रही है। आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार को एक दाम बांधो नीति अख्तियार करनी होगी कि जो अनाज किसान के खेत में पैदा होता है वह अनाज पूरे एक साल तक सवा गुना दाम के अंदर ही बिकेगा। अगर किसान ने 153 रु० क्विंटल अपना गेहूं बेचा है तो सवा गुना दाम के अन्दर ही वह चाहे तो फिर अनाज खरीद सकता है और जो कारखाने में चीजें पैदा होती हैं और जो उनका लागत खर्च है वह ड्योढ़ा के अन्दर ही बिकेगी। किसानों के खेतों में पैदा होने वाली वस्तुओं के दामों में पूरे एक साल में यानि फसल आने से लेकर दूसरी फसल आने तक सवा गुना से ज्यादा अन्तर न हो और जो कारखानों में चीजें पैदा हो रही हैं, उनके मैन्युफेक्चरिंग गुड्स के दाम लागत खर्च से डेढ़ गुना के अंदर ही रहें। अगर यह नीति सरकार बनाये तो हिंदुस्तान में कृषि और औद्योगिक जगत में एक संतुलन स्थापित होगा।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि टर्म्स आफ ट्रेड, 12 मार्च, 1980 को श्रीमती इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने फैसला किया कि किसानों के खेतों में पैदा होने वाली चीजों और कारखानों में पैदा होने वाली चीजों के दामों में पैरिटी इस्टेबलिश की जाएगी, इसके लिये मैं भारत के करोड़ों किसानों की तरफ से पूज्यनीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। जिनके कारण यह प्रिंसिपल आफ पैरिटी 1980 में तय हुई। क्या पैरिटी का सिद्धांत लागू हो रहा है? 1985 में किसानों का नाम लेने वाले आजकल जो उनके मसीहा बन रहे हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह, उनके जमाने में एडमिनिस्टर्ड प्राइस लोहे के दाम 300 रुपये क्विंटल से बढ़कर 800 रुपये क्विंटल हो गये थे। गेहूं के भाव ढाई रुपये क्विंटल बढ़े। यह पैरिटी है? यह केन्द्रीय मंत्रिमंडल का फैसला है कि लोहे का दाम-तिगुना कर दो और गेहूं के भाव ढाई रुपये क्विंटल बढ़ा दो। पूज्य इन्दिरा जी को मैं फिर बधाई देना चाहूंगा कि 1980 में गेहूं के भाव दस रुपये क्विंटल बढ़े, 1981 में दस रुपये क्विंटल बढ़े, 1982 में दस रुपये क्विंटल बढ़े और 1983 में दस रुपये क्विंटल बढ़े। लगातार दस रुपये

क्विंटल के हिसाब से गेहूं के भाव बढ़े लेकिन इन्दिरा जी के मरने के बाद पिछले 5 वर्ष में एक बार भी 10 रुपये क्विंटल गेहूं के दाम नहीं बढ़े । जबकि मैन्यूफैक्चरर्स गुड्स के दाम दुगुने तिगुने बढ़े । सीमेंट, लोहा और कपड़ा जो भी किसान इस्तेमाल करता है सब के दाम दुगुने और तिगुने बढ़े । आप हरियाणा और पंजाब से उत्तर प्रदेश और बिहार का मुकाबला मत कीजिए । उत्तर प्रदेश का किसान तो कर्ज में पैदा होता है और कर्ज में ही जी रहा है और कर्ज में ही मर रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव में श्याम लाल यादव जी और हरिकृष्ण शास्त्री जी के साथ जाने को तैयार हूं । 90 प्रतिशत किसान कर्जदार है । कर्ज में इतना लदा हुआ है कि अगर उनका घर गिर गया तो वह घर बना नहीं सकता, अगर बेटी की शादी है तो खेत बेचकर ही शादी करनी होगी । बुनियादी बात यह है कि 1947 में जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ उस जमाने में किसान का खेत दस बीघे का था । अपने बैल से हल चला कर खेत जोतता था। अपने बैल, गाय, भैंस के गोबर को अपने खेत में खाद के रूप में इस्तेमाल करता था और अपने कुएं और रहट से पानी लेता था । फिर खुद काट कर अनाज अपने घर लाता था। लेकिन आज औद्योगिक इंडस्ट्रलाइजेशन होने के बाद चाहे सीमांत किसान हो, चाहे मारीजनल किसान हो, चाहे लघु किसान हो, इनकी 72 परसेंट की संख्या है इन्हें अपने खेत को ट्रेक्टर से जुतवाना पड़ता है नहर और ट्यूबवैल से पानी लेना पड़ता है पेस्टीसाइड्स और इन्सैक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। फर्टीलाइजर का इस्तेमाल करना पड़ता है । अगर बाढ़ आ गयी तो पूरी फसल नष्ट हो गयी। सूखा पड़ गया तो पूरी फसल नष्ट हो गयी। जो कोआपरेटिव बैंक्स है, रजिस्टर्ड बैंकों से कर्जा लेकर ट्रेक्टर से जुताई करता है, फर्टीलाइजर का इस्तेमाल करता है, पेस्टीसाइड्स का इस्तेमाल करता है, इन्सेक्टीसाइड्स का इस्तेमाल करता है। अगर फसल बाढ़ और सुखाड़ से नष्ट हो गयी तो जितना कर्जा उसने लिया 12 या 14 परसेंट के हिसाब से, अपने घर गिरवी रख कर वह बम्बई या कलकत्ता चला जाता है । यह आज के किसानों की हालत है। खेती करने वाला छोटा किसान लगातार अपनी जमीन बेच रहा है । 4 बीघा, 6 बीघा या तीन बीघा पर खेती करने वाला किसान लगातार अपनी जमीन बेच कर भूमिहीन मजदूर बनता जा रहा है । यह उत्तर प्रदेश और बिहार की हालत में बता रहा हूं । इस हालत में अगर हिन्दुस्तान को जीवित रखना है तो देश की कृषि के प्रश्न पर बहुत बुनियादी रूप से चिंतन करना होगा । इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी । 20 दिसम्बर, 1984 को बम्बई में श्री राजीव गांधी देश के प्रधान मंत्री ने घोषणा की कि अब हिन्दुस्तान में किसानों के खेतों में पैदा होने वाली वस्तुओं के दाम तय करने के लिए एग्रीकल्चर्स प्राइस कमीशन नहीं होगा बल्कि एग्रीकल्चर्स कास्ट्स एंड प्राइस कमीशन होगा । अब एग्रीकल्चर्स सामानों की कास्टिंग होगी पहले, तभी प्राइसिंग होगी । कास्टिग होगी तभी प्राइसिंग होगी । 84 में प्रधान मंत्री ने घोषणा की। सन् 1984 में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया । श्री वीरेन्द्र वर्मा, श्री रामचन्द्र विकल और मैंने इस तरफ सदन का ध्यान दिलाया। उस समय श्री राव वीरेन्द्र सिंह कृषि मंत्री थे । उन्होंने कहा कि छः महीने के अन्दर एग्रीकल्चरल कास्ट और प्राइस कमीशन बन जाएगा । बाद में राव वीरेन्द्र सिंह चले गये । फिर बूटा सिंह आये । फिर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया तो उन्होंने घोषणा कि कि एक महीने के अन्दर एग्रीकल्चरल कास्ट और प्राइस कमीशन बन जाएगा । उसके बाद श्री योगेन्द्र मकवाना कृषि मंत्री बने । उन्होंने कहा कि अगले सेशन के पहले यह कमीशन बन जाएगा । अब ये लोग मंत्री नहीं रहे हैं। अब श्री भजन लाल जी कृषि मंत्री हैं । पिछले चार सालों से यह कमीशन नहीं बना है । आप इस संबंध में कल क्या जवाब देंगे, हम नहीं जानते हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि आप मंत्रिमंडल की बैठक बुलाकर प्रधान

[श्री कल्पनाथ राय]

मंत्री से बातचीत कर इस बात की घोषणा करें कि एग्रीकल्चरल कास्ट एण्ड प्राइस कमीशन अब बना दिया गया है। मंत्रिमंडल के मंत्रियों ने सदन में बयान दिया, लेकिन फिर भी उस पर अमल नहीं हो रहा है। आखिर सदन में बयान देने का क्या मतलब होता है? यह देश का सबसे बड़ा सदन है। पहले सदन में कहा गया कि एक महीने में कमीशन बन जाएगा, अगले सेशन से पहले बन जाएगा, लेकिन कमीशन अभी तक नहीं बना है। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। मैं श्री भजन लाल जी से प्रार्थना करना चहता हूं कि जब श्री जगजीवन राम जी षि मंत्री बने थे तो भगवान की कृपा होती थी। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि अब श्री भजन लाल जी कृषि मंत्री बने हैं, अब हिन्दुस्तान में सूखा नहीं पड़ेगा। देश फिर से धनधान्य से भर जाएगा, हमें विदेशों से अन्न नहीं मंगाना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप कास्ट एण्ड प्राइस कमीशन की घोषणा करें।

आखिरी बात कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं। कृषि के संबंध में आरदणीय श्री राजीव गांधी ने कहा कि डेवलपमेंट और प्लानिंग का काम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करना होगा। प्रधान मंत्री की यह घोषणा बड़ी सराहनीय है। लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो हमारी नौकरशाही जो हमारे नेता लोग हैं, उनको अमल में लाना पड़ेगा हिन्दुस्तान कृषि प्रधान देश है। यहां की ज्यादातर आबादी गांवों में रहती है। खेती के अलावा उनके पास अन्य कोई काम नहीं होता है। लेकिन अब स्थिति यह हो गई है कि कृषि लाभप्रद नहीं रह गई है। यही कारण है कि गांवों के किसानों के लड़के शहरों में 200 रुपए की नौकरी के लिए भागते फिरते हैं। दिल्ली में दर-दर की ठोकरें खाने के लिए आते हैं। आज खेती घाटे का सौदा हो गया है। आज लोग खेती को छोड़कर शहरों की तरफ भाग रहे हैं। आप मेरे साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में चलिए। वहां पर 90 प्रतिशत लोग खेती को छोड़कर शहरों की तरफ जा रहे हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि हमें अपने देश में ग्राम स्वराज्य लाना है, स्वावलम्बी बनना है। श्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान, जय किसान का नारा दिया था। अभी विकल जी पूछ रहे थे कि भगवान कहां रहते हैं? भगवान् मंदिर में नहीं मिला, मस्जिद में नहीं मिला, भगवान गुरुद्वारे में भी नहीं मिला, और न ही भगवान कुरान में मिला न बाइबल में मिला, हिन्दुस्तान का भगवान तो गांवों के खेतों में हल चलाते हुए मिलता है, जो अपना पसीना बहाकर हिन्दुस्तान के करोड़ों लोगों को अन्न देता है और जिस के बेटे सीमा पर प्रहरी बनकर देश की गरिमा और गौरव की रक्षा करते हैं उसके बेटे आजादी की लड़ाई के दौरान फांसी के तख्ते पर झूले और इन्हीं किसानों के बेटों ने अंग्रेजी सरकार से लोहा लिया और इन्हीं किसान के बेटों ने भारत में आजादी का शंखनाद किया। इन्हीं किसानों के बेटे आज सीमाओं पर बार्डर सेक्योरिटी फोर्स और सी०आर० पी०एफ० में है और हिन्दुस्तान की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं।

आखिर में उपसभाध्यक्ष महोदय, लैंड रिफार्म के बारे में कहना चाहूंगा। 1986 में प्रधान मंत्री जी ने पार्लियामेंटरी पार्टी में बोलते हुए कहा कि लैंड रिफार्म विल बी इम्प्लीमेंटेड आन वार फुटिंग बेसिस। भूमि सुधार युद्ध स्तर पर लागू किया जायेगा। आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, भूमि सुधार के संबंध में हमारी सरकार का, केन्द्रीय सरकार का डाइरेक्टिव राज्य सरकारों को क्या है? जो हमारे देश के अन्दर राजे-रजवाड़े हैं, सामंत और पूंजीपति हैं, जो बड़े बड़े ताल्लुकेदार, जागीरदार हैं, जो आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ थे, हिन्दुस्तान के 242 प्रिवीपर्स वाले राजा-रजवाड़े अंग्रेजों के साथ थे। एक भी हिन्दुस्तान के पिर्वी पर्स होल्डर राजा ने आजादी की लड़ाई

में हमारा साथ नहीं दिया। हिन्दुस्तान में हजारों हजार जागीरदार, हजारों हजार ताल्लुकेदार और हजारों हजार जमीनदार जो हैं उन्होंने उस समय अंग्रेजों का साथ दिया। उन्होंने गांधी और नेहरू का साथ नहीं दिया।

श्री राम चन्द्र विकल : राजा महेन्द्र प्रताप ने उनका साथ नहीं दिया और विदेशों में जाकर अंग्रेजों के खिलाफ कार्य किया।

श्री कल्पनाथ राय : पिर्वी पर्स पाने वाले 242 राजाओं में से किसी ने हमारा, साथ नहीं दिया। पिर्वी पर्स में कह रहा हूं, इसको पाने वाले 242 राजा-रजवाड़ों में से एक ने भी आजादी की लड़ाई में गांधी नेहरू का साथ नहीं दिया। आजादी की लड़ाई के अन्दर ये जागीरदार, जमीनदार नेहरू गांधी के खिलाफ थे और उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। ये ही लोग आज एक कुंडली मारकर हिन्दुस्तान की जमीन पर, कानून बना है कि 18 एकड़ से ज्यादा जमीन कोई नहीं रख सकता लेकिन ये 4 हजार एकड़, 10 हजार एकड़, 15 हजार एकड़, 18 हजार एकड़ जमीन राजा मांडा, राजा फलाना. देश के राजा-रजवाड़े, ताल्लुकदार रखे हुए हैं और राज सत्ता में आकर, कांग्रेस पार्टी के अन्दर, कांग्रेस सरकार में प्रभावशाली पदों पर कब्जा जमाकर बैठे हैं जिसके कारण इस तरह की कठिनाइयां हो रही हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जितने भी लैंड होल्डर्स हैं, जो लोग लैंड रिफार्म है के विरोधी हैं, जो भूमि सुधार के दुश्मन हैं, जो इस तरह के राजा-रजवाड़े, जमींदार और ताल्लुकदार हैं उनकी सारी जमीनें जो 18 एकड़ से ऊपर हैं उसको सरकार एक आर्डिनेंस जारी करके जब्त करें और उस जमीन को मार्जिनल फारमर्स, सीमान्त किसानों में उस जमीन का बंटवारा करे ताकि करोड़ों, करोड़ इंसान जो बिना खेत के हैं वे अपने श्रम, से, अपनी मेहनत से उस जमीन पर अन्न की पैदावार करें और जो आज इस देश में 150 मिलियन अनाज पैदा हो रहा है वह चीन के बराबर, 4 सौ मिलियन टन पैदा हो सके और भारत एक शक्तिशाली समृद्धिशाली, समाजवादी राष्ट्र बन सके। राजीव गांधी जी ने नारा दिया है कि लैंड रिफार्म्स बिल की इम्प्लीमेंटेड आन द वार फुटिंग बेसिस अर्थात भूमि सुधार का युद्धस्तर पर लागू किया जायेगा। मुझे विश्वास है कि हमारे कृषि मंत्री श्री भजनलाल जी, श्री श्यामलाल यादव जी और श्री शास्त्री जी प्रधान मंत्री के इस कथन को कि हम भूमि सुधार को युद्ध स्तर पर लागू करेंगे, इसको पूरा करने के लिये प्रदेश सरकारों को डाइरेक्टिव देंगे ताकि हम आजादी की लड़ाई के अतीत को सामने रखकर भविष्य के सुनहरे दिनों का निर्माण कर सकें और भारत एक शक्तिशाली देश बन सके। इन शब्दों के साथ धन्यवाद।

SHRI GHULAM RASOOL MATTO : Mr. Vice-Chairman, Sir, for a change I will speak in Urdu.

जनाबेआली, भजनलाल जी के मुत्तलिक कई लोग जो भी राय रखते हों मगर मैं उनको ऐसा लीडर मानता हूं जो कि प्रताप सिंह कैरों और हमारे कश्मीर के बख्शी गुलाम मुहम्मद के जुमले में आते हैं। ये लोग अगर जाती दिलचस्पी लेकर कोई काम करना चाहते थे तो वे वह काम पूरा करके दिखाते थे। मैं श्री भजन लाल को इन्हीं शख्सों में गिनता हूं। यह

7.00 P.M.

चापलूसी नहीं है बल्कि हकीकत है। जनाबेवाला एग्रीकल्चर का जो महकमा है इतना बड़ा है। शास्त्री जी हमारे रिसर्च एंड डवलपमेंट विंग को देखते हैं मुझे नहीं मालूम कि उनको वक्त होता होगा घर में बच्चों के साथ बैठने का इतनी बड़ी रिसर्च करने की जरूरत है और कर रहे हैं। इस तरह से श्याम लाल यादव जी अपना महकमा सम्भाल रहे हैं और सैंकड़ों ऐसे इदारे हैं जो इनकी तरफ देख रहे हैं। मगर जो चीज कल्पनाथ राय जी ने कही वह सही है कि लीडरशिप की जरूरत इस मिनिस्टरी में और वह लीडरशिप मुझको भजन लाल जी में नजर आ रही है वह झलक उस लीडरशिप की जरूर दिखाएंगे वह करके दिखायेंगे और दिखाना क्या है। मैं एक दो चीजों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं आपका समय ज्यादा न लेते हुए मैं कनसलटेटिव कमेटी जो प्लानिंग

मिनिस्टरी की है उसका मैम्बर पिछले 6 साल से रहा हूं । हम जब इस मसले पर बहस करते थे एग्रीकल्चर के मसले पर तो दो चीजों की तरफ हर वक्त हम ध्यान देते थे प्लानिंग कमीशन के जो मैम्बर थे और जो दूसरे मैम्बर थे वह दो चीजों की तरफ हम ध्यान दिलाते थे । यह ठीक है कि हमने गेहूं के मामले में अनाज के मामले में तरक्की की है मगर जैसे वर्मा जी और दूसरे मैम्बरों ने कहा है हम अभी बहुत पीछे हैं दूसरे मुल्कों से हमें बहुत आगे बढ़ना है । मगर दो चीजें ऐसी हैं जिनकी तरफ मैं भजन लाल जी की तवज्जोह दिलाना चाहता हूं और यह चाहता हूं कि वह वही एरियाज है जिसको वह गोद ले लें चाहे वह ईस्टर्न यू० पी० का हिस्सा ले लें वेटर्न बिहार का हिस्सा ले लें मध्य प्रदेश का हिस्सा ले लें वह गोद ले लें । मैं यह चाहूंगा कि वे मुझे इस बात का इत्मीनान दें कि इन दो चीजों में हम खुद कफालत हासिल कर लेंगे । जैसे कि मैंने यह अर्ज किया कि यह मामला हमारी कनसलटेटिव कमेटी में उठता है वह पल्सेज और एडिबल आयल्ज । यह दोनों चीजें इतनी बहुत सख्त जरूरी चीजें हैं कि आम आदमी के लिए हिन्दुस्तान की जो आबादी है उसके लिए इससे प्रोटीन मिल सकते हैं सिर्फ दालों के जरिये से मिलते हैं और एडिबल आयल तो ऐसी चीज है कि छोटे से छोटे और बड़े से बड़ा आदमी इसको इस्तेमाल करता है और इस्तेमाल करना चाहिये सवाल यह पैदा होता है कि हमने रिसर्च भी की और इसमें बढ़ावा भी किया हमने तरक्की भी की मैं मानता हूं तरक्की की है मगर मैं यह चाहता हूं कि श्री भजन लाल जी इस एरिया को गोद ले लें जिस तरह से एक बच्चे को गोद लिया जाता है इस तरह से एस एरिया को गोद ले लें और मुझे दिला दें कि पल्सेज में हम खुद कफालत कब तक हासिल कर सकते हैं और आयल सीड्ज में हम कब तक खुद कफालत हासिल कर सकते हैं । मगर जिस तरह से प्रताप सिंह कैरों का नाम ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए जाता है उसी तरह से एडिबल आयल के सिलसिले में और पल्सेज में रेवोल्यूशन के सिलसिले में भजन लाल जी को मैं याद करूंगा और हमारी तमाम कौम जो आने वाली नस्लें हैं उनको याद करेंगी । जब वे इस मामले में जवाब दें तो हमें अपनी प्लान के बारे में बताएं सिर्फ रिसर्च और डवलपमेंट को फिगर्ज में न जाएं और यह कहें कि कैसे इसको किया जाएगा और गोद ले कर इन चीजों में खुद कफालत कर सकते हैं । यह चीजें बहुत जरूरी हैं इसलिए मैं उनका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं । दूसरी बात जिसकी तरफ मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि मुझे पिछले हफ्ते पंजाब जाने का इत्तेफाक हुआ था । मैं शाने पंजाब गाड़ी से जा रहा था और हरियाणा से गुजरा तो दिल बहुत खुश हुआ लहलहाते हुए खेतों में फसल काटी जा रही थी और यह हरियाणा में चीफ मिनिस्टर रहे हैं । मैं उनको दाद देता हूं कि हरियाणा में मैंने देखा कि काफी अच्छी फसल हो रही है जबकि कुछ साल पहले जमीन बंजर थी अब उसी इलाके में लहलहाते खेत दिखायी देते हैं । मैं पंजाब में लुधियाना गया और लुधियाना में मेरे एक दोस्त हैं उनका ड्राइवर है जो सरदार जी है मैंने पूछा कि सरदार जी फसल का क्या हाल है तो उसने कहा कि वाईगुरू की कृपा है बहुत अच्छी है हालांकि पिछले साल की जो पैदावरा थी उस पिछले साल से भी ज्यादा पैदावरा मुझे अपने घर में वसूल हुई है और दो दिन पहले ही मैं वहां से आया हूं । पिछले साल से पिछले साल जो पैदावार हुई थी वह बारिश की वजह से खराब हो गई थी लेकिन इस बार 20-25 फीसदी फसल ज्यादा मिली है जो पिछले साल से पहले मिली थी यह वाईगुरु जी की कृपा है । मैं भजन लाल जी से कहता हूं कि पंजाब और हरियाणा ऐसे इलाके हैं कि जो आपके नजदीक एक मिसाल बन सकते है । मगर वह मिसाल भी अपनी जगह इतनी काबिले रश्क मिसाल नहीं है । मसलन अगर इंडिया की धान की पैदावार 1417 किलोग्राम पर हेक्टेयर है तो चायना की 5271 है, जापान की 6441 है इजिप्ट जैसे मुल्क की 5310 है और मुझे

थोड़ी सी शर्म आती है कि एक हमारे हमसाये देश पाकिस्तान की 2560 है और हमारे यहां केवल 1417 प्रति हैक्टेयर है। इसी तरह से बंगलादेश भी हमारे से बहुत ऊंचा है 2000 के करीब उसकी भी है। जहां तक गेहूं का ताल्लुक है उसमें 7000 तक गया है मगर हमारा 1870 से ज्यादा नहीं हुआ। मैं यह इसलिए कहता हूं कि जब हम 1870 गेहूं के लिए तथा 1417 धान के लिए एक स्टैंडर्ड मानते हैं जो दुनिया के और मुल्कों से कम है तो मैं भजन लाल जी से अर्ज करूंगा कि आप इस मुल्क के दूसरे हिस्सों को जैसा मैंने कहा कि आइडेंटिफाई कर लें जैसे ईस्टर्न यू. पी., वेस्टर्न बिहार या मध्य प्रदेश का कोई हिस्सा गोद ले लें. . . (व्यवधान) काश्मीर ले लें, जम्मू ले लें, जिसमें आप कम से कम उतनी ही पैदावार दिलवा दें जितनी पंजाब और हरियाणा में दिलाते हैं हालांकि जैसा मैंने अर्ज किया कि पंजाब और हरियाणा में भी पैदावार कम है दूसरे मुल्कों में 6 गुना ज्यादा है, चाइना और जापान में चार पांच गुना ज्यादा है। मैं यह अर्ज करूंगा कि आपके पास रिसर्च डेवलपमेंट भी है और आपके पास लेबोरेट्रीज भी है लेकिन एक दिल होना चाहिए। जिस तरह से एक आदमी किसी को गोद लेकर अपने बच्चे से ज्यादा प्यार करता है तो आपको एक हिस्सा लेना पड़ेगा ताकि वेस्टर्न बिहार, ईस्टर्न यू.पी., मध्य प्रदेश या पंजाब और काश्मीर के लोग यह समझ लें कि भजन लाल जी ने हमको दिखा दिया कि जहां हमारी प्रति एकड़ इतनी पैदावार होती थी वहां आज इतने गुना हो गयी है और यह उनकी मेहरबानी है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि भजन लाल जी को इसकी तरफ खास ध्यान देना पड़ेगा और अगर ये जाती तौर पर ध्यान देंगे तो मेरी पहली आरजू और तमन्ना है कि हम पल्सेज और एडीबुल आयल सीड्स में खुद कफील होंगे फिर मुझे भजन लाल जी जो कहेंगे मैं मानने के लिए तैयार हूंगा, उनके रिसर्च वाले, मिनिस्ट्री वाले जो कुछ भी कहेंगे अगर मुझे और कौम को कल के जवाब में यह इत्मीनान दे दें कि वे कब तक एडीबुल आयल और पल्सेज के मामले मुल्क को खुद कफील बतायेंगे। मैं जनाब इसलिए यह जोर नहीं देता हूं बल्कि मुझे यह तवक्का है कि जो हमारी गेहूं और चावल की पैदावार हो रही है उसके हिसाब से आने वाले दिनों में अगर खुदा न खास्ता कोई ड्राउट नहीं हुआ तो हम खुद कफील हो जायेंगे। हम गेहूं में खुद कफील रहे हैं पिछले साल और इस साल 10 लाख टन गेहूं बरामद किया है वह भी मुश्किल से क्योंकि इस साल सौ सालों में पहली दफा भयानक सूखा पड़ा है जो कभी आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर यह मुल्क बचा है तो इन्हीं लोगों की मेहरबानी से बचा है जिन लोगों ने हमें इतनी पैदावार दी नहीं तो यहां भी वही हालत होती जो इथियोपिया या अफ्रीका के दूसरे मुल्कों में है। मगर मैं इसी तरह से यह अर्ज करूंगा कि इसके साथ एडीबुल आयल और पल्सेज की भी पैदावार हो।

मेरे पास समय कम है लेकिन मैं आखिर में एक बात कहना चाहता हूं कि यह बात सही है कि किसान का भी ख्याल रखना पड़ेगा। पिछली दफा इसी हाउस में जनाब सुख राम जी ने गेहूं और तिलहन की कीमतों के बारे में कुछ आंकड़े यहां पर पेश किये थे, बहस हो रही थी कि फ्लोर मिल्स को इश्यू प्राइस कितना होगा और उनकी जुबान से हमको यह पता लगा—मिनिस्टर साहब जरा तवज्जो फरमाये कि जहां हम 173 रुपये उस गरीब किसान को दे रहे हैं। तो 163 रुप०? हमारा हैंडलिंग चार्जेज होता है, जो एफ. सी. आई. हैंडलिंग चार्जेज स्टोर करने या लाने ले जाने में करती है वह 163 रुपया खर्च होता है, इसकी तरफ भी ध्यान देना होगा। मैं इस वास्ते पूछना चाहता हूं कि अगर यह आटा एक कंज्यूमर को किसी भाव में मिलता है उसमें 163 रुपये प्रति क्विंटल का खर्च जो एफ. सी. आई. करती है वह शामिल होता है। अगर उस खर्च में कमी करके दिखायें भजन लाल जी तो वह रकम किसान को दे देंगे। अगर 163 में से 60 रुपये कम कर दें तो 60 रुपये 170 की बजाय 230 रुपये किसान को दे सकते

[श्री गुलाम रसूल मट्टू]

हैं क्योंकि किसान रीढ़ की हड्डी है, किसान हमारी तमन्नाओं का मरकज़ है। हमारे लिए किसान ही सब कुछ है और इस चीज के लिए किसान की तरफ ध्यान देना होगा। मैं आखिर में अल्लामा इकबाल के शेर के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं, कल्पनाथ जी ध्यान फरमाइये और भजन लाल जी का ध्यान भी आकर्षित करना चाहता हूं और अल्लामा इकबाल के शेर के साथ मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूं और वह यह है कि,

'जिस खेत से दहकान को मयस्सर न हो रोज़ी'
उस खेत के हर खोश-ए-गंदम को जला दो।"

इन्हीं अलफाज के साथ मैं जनाब भजन लाल जी से दरख्वास्त करूंगा कि वह अपने जवाब में मेरे इन चंद मौजूयात का तसल्ली-बख्श जवाब दें ताकि मुल्क और कौम को इतमीनान हो जाए कि हम ऐसी कौम हैं कि जिसमें एतमादी है खुद-एतमादी है और हमें जो काम करना चाहिए वह हम करके दिखायेंगे और भजन लाल जी की क्यादत में करके दिखायेंगे। धन्यवाद।

†[جناب عالی - بھجن لال جی کے متعلق کئی لوگ جو بھی رائے رکھتے ہوں - مگر میں انکو ایسا لیڈر مانتا ہوں جوکہ پرتاپ سنگھ کیروں اور ہمارے کشمیر کے بخشی غلام محمد کے زمرے میں آتے ہیں - یہ لوگ اگر ذاتی دلچسپی لیکر کوئی کام کرنا چاہتے تھے تو وہ اس کام کو پورا کرکے دکھاتے تھے - میں شری بھجن لال کو انہیں اشخاص میں گنتا ہوں - یہ چاپلوسی نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے - جناب والا - ایگریکلچر کا جو محکمہ ہے اتنا بڑا ہے - شاستری جی ہمارے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ونگ کو دیکھتے ہیں - مجھے نہیں معلوم کہ انکو وقت ہوتا ہوگا کہ پھر بچوں کے ساتھ بیٹھنے کا اتنی بڑی ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے اور کر رہے ہیں - اس طرف سے شام لال یادو جی اپنا محکمہ سنبھال رہے ہیں اور سینکڑوں ایسے ادارے ہیں - جو انکی طرف دیکھ رہے ہیں - مگر جو چیز کلپناتھ رائے جی نے کہی وہ صحیح ہے کہ لیڈر شپ کی ضرورت ہے اس منسٹری میں اور وہ لیڈرشپ مجھے بھجن لال جی میں نظر آرہی ہے وہ جھلک اس لیڈر شپ کی ضرور دکھائینگے وہ کرکے دکھائینگے اور دکھانا کیا ہے - میں ایک دو چیزوں کی طرف دھیان دلانا چاہتا ہوں - آپکا وقت زیادہ نہ لیتے ہوئے - میں کنسلٹیٹیو کمیٹی جو پلاننگ منسٹری کی ہے اسکا ممبر پچھلے چھ سال سے رہا ہوں - ہم جب اس مسئلے پر بحث کرتے تھے ایگریکلچر کے مسئلے پر تو دو چیزوں کی طرف ہر وقت دھیان دلاتے تھے - یہ ٹھیک ہے - کہ ہم نے گیہوں کے معاملے میں اناج کے معاملے میں ترقی کی ہے مگر جیسے ورما جی - اور دوسرے ممبروں نے کہا ہے کہ ہم ابھی بہت پیچھے ہیں

† [ ] Transliteration in Arabic Script of the Urdu speech delivered "by Shri Ghulam Easool Matto.

دوسرے ملکوں سے تو ہمیں آگے
بڑھنا ہے - مگر دو چیزیں ایسی
ہیں جن کی طرف میں بھجن لال
جی کی توجہہ دلانا چاہتا ہوں اور
یہ چاہتا ہوں کہ وہ بھی ایریاز ہے
جسکو وہ گود لے لیں تو جائے وہ
ایسٹرن یو - پی - کا حصہ لے لیں
ویسٹرن بہار کا حصہ لے لیں یا
مدھیہ پردیش کا حصہ لے لیں - وہ
گود لے لیں - میں یہ کہنا چاہونگا
کہ وہ مجھے اس بات کا اطمینان
کرا دیں - کہ ان دو چیزوں میں
ہم خود کفالت حاصل کر لیں گے -
جیسے کہ میں نے یہ عرض کیا کہ
یہ معاملہ ہماری کنسالٹیٹیو کمیٹی
میں اٹھا ہے - وہ ہے پلسیز اور
ایڈیبل آئل کا - یہ دونوں چیزیں
اتنی بہت سخت ضروری چیزیں
ہیں- کہ عام آدمی کیلئے ہندوستان
کی جو آبادی ہے اسکے لئے اس سے
پروٹین مل سکتے ہیں اور ملتے ہیں
صرف دالوں کے زریعہ سے ملتے ہیں
اور ایڈیبل آئل تو ایسی چیز ہیں کہ
چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑا آدمی
اسکو استعمال کرتا ہے- اور استعمال کرنا
چاہئے - سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ
ہم نے ریسرچ بھی کی اور اسمیں
بڑھاوا بھی ہوا ہے - ہم نے ترقی
بھی کی ہے - میں مانتا ہوں ترقی
کی ہے - مگر میں یہ چاہتا ہوں
کہ شری بھجن لال جی اس ایریا
کو گود لے لیں جس طرح ایک

بچے کو گود لیا جاتا ہے - اس
طرح اس ایریا کو گود لے لیں اور
مجھے دکھا دیں - کہ پلسیز میں
ہم خود کفالت کب تک حاصل
کر سکتے ہیں - اور آئل سیڈز میں
ہم کب تک خود کفالت حاصل
کرسکتے ہیں - مگر جسطرح سے
پرتاپ سنگھ کیروں کا نام گرین ریوو
لوشن کیلئے لیا جاتا ہے اسی طرح
سے آئل سیڈز کے سلسلے میں اور
پلسیز میں ریوولوشن کے سلسلے میں
بھجن لال جی کو میں یاد کرونگا
اور ہماری تمام قوم جو آنے والی
نسلیں ہیں انکو یاد رکھیں گی -
جب وہ اس معاملے میں جواب
دیں تو ہمیں اپنی پلان کے بارے
میں بتائیں صرف ریسرچ اور
ڈیولوپمنٹ کی فیگرس میں نہ
جائیں - اور یہ کہیں کہ کیسے
اسکو کیا جائیگا اور گود لیکر ان
چیزوں میں خود کفالت کر سکتے
ہیں یہ چیزیں بہت ضروری ہیں
اسلئے میں انکا دھیان اس طرف
دلانا چاہتا ہوں - دوسری بات
جسکی طرف میں انکا دھیان
دلوانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے
پچھلے ہفتہ پنجاب جانے کا اتفاق
ہوا تھا - میں شان پنجاب
ایکسپریس سے جا رہا تھا - اور
ہریانا سے گذرا تو دل بہت خوش
ہوا لہلہاتے ہوئے کھیتوں میں فصل
کاٹی جا رہی تھی - اور یہ ہریانہ

[چودھری غلام رسول متو]

میں چیف منسٹر رہے ہیں - میں انکو داد دیتا ہوں کہ ہریانہ میں میں نے دیکھا کہ کافی اچھی فصل ہو رہی ہے جبکہ کچھ سال پہلے وہ زمین بنجر تھی - اب اسی علاقے میں لہلہاتے ہوئے کھیت دکھائی دیتے ہیں - میں پنجاب سے لدھیانہ گیا اور لدھیانہ میں میرے ایک دوست ہیں انکا ڈرائیور سردار ہے میں نے پوچھا سردار جی فصل کا کیا حال ہے تو اسنے کہا کہ واہے گرو کی کرپا ہے بہت اچھی ہے - حالانکہ پچھلے سال کی جو پیداوار تھی اس سے پچھلے سال بھی زیادہ پیداوار مجھے اپنے گھر میں وصول ہوئی ہے اور دو دن پہلے ہی میں وہاں سے آیا ہوں - پچھلے سال جو پیداوار تھی وہ بارش کی وجہہ سے خراب ہو گئی تھی لیکن اس بار بیس پچیس فیصدی فصل زیادہ ملی ہے - جو پچھلے سال سے پہلے ملی تھی یہ واہے گرو جی کی کرپا ہے -

میں بھجن لال جی سے کہتا ہوں کہ پنجاب اور ہریانہ ایسے علاقے ہیں - کہ جو آپ کے نزدیک ایک مثال بن سکتے ہیں مگر وہ مثال بھی اپنی جگہہ اتنی قابل رشک مثال نہیں ہے - مثلاً گر انڈیا کی دھان کی پیداوار ۱۳۱۷ کلوگرام پر ہیکٹیر ہے تو چائنا کی ۵۲۷۱ ہے - جاپان کی ۷۳۴۱ ہے اجیپٹ کی ۵۳۱۰ ہے اور مجھے تھوڑی سی شرم آتی ہے کہ ایک ہمارے ہمسائے ملک پاکستان کی ۲۵۶۰ ہے - اور ہمارے یہاں صرف ۱۳۱۷ پر ہیکٹیر ہے - اسی طرح سے بنگلہ دیش ہمارے سے بہت اونچا ہے - ۲۰۰۰ کے قریب اسکی بھی ہے - جہاں تک گیہوں کا تعلق ہے - اسمیں بھی ۷۰۰۰ تک گیا ہے - مگر ہمارا ۱۸۷۰ سے زیادہ نہیں ہوا - میں یہ اسلئے کہتا ہوں کہ جب ہم ۱۸۷۰ گیہوں کیلئے اور ۱۳۱۷ دھان کیلئے اسٹینڈرڈ مانتے ہیں جو دنیا کے اور دوسرے ملکوں سے کم ہے - تو میں بھجن لال جی سے عرض کروں کہ آپ اس ملک کے دوسرے حصوں کو آئڈنٹیفائی کر لیں - جس سے کہ ایسٹرن یو - پی - ویسٹرن بہار - یا مدھیہ پردیش کا کوئی حصہ گود لے لیں .... ((مداخلت)) ......

کشمیر لے لیں - جموں لے لیں - جسمیں آپ کم سے کم اتنی ہی پیداوار دلوا دیں جتنی پنجاب اور ہریانہ میں دلاتے ہیں - حالانکہ جیسا میں نے عرض کیا کہ پنجاب اور ہریانہ میں بھی پیداوار کم ہے - دوسرے ملکوں میں چھ گنا زیادہ رہتا چائنہ اور جاپان میں چار پانچ گنا زیادہ ہے - میں یہ عرض کروں کہ آپکے پاس ریسرچ ڈیولپمنٹ

بھی ہے اور آپکے پاس لیبوریٹریز بھی ہے - لیکن ایک دل ہونا چاہئیے - جسطرح ایک آدمی کسی کو گود لیکر اپنے بچے سے زیادہ پیار کرتا ہے تو آپکو ایک حصہ لینا پڑیگا - تاکہ ایسٹرن یو - پی - ویسٹرن بہار مدھیہ پردیش یا پنجاب اور کشمیر کے لوگ یہ سمجھ لیں کہ بھجن لال جی نے ہم کو دکھا دیا کہ جہاں ہماری دھرتی ایکڑ اتنی پیداوار ہوتی تھی وہاں آج اتنے گنا ہو گئی ہے - اور یہ انکی مہربانی ہے - تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھجن لال جی کو اسکی طرف خاص دھیان دینا پڑیگا - اور اگر یہ ذاتی طور پر دھیان دینگے تو میری آرزو اور تمنا یہ ہے کہ ہم پلسیز اور آئل سیڈز میں خود کفیل ہونگے - پھر مجھے بھجن لال جی جو کہیں گے میں ماننے کو تیار رہونگا - انکے ریسرچ منسٹری والے جو کچھ بھی کہیں گے اگر مجھے اور قوم کو کل کو جواب میں یہ اطمینان دیدیں کہ وہ کب تک ایڈیبل آئل اور پلسیز کے معاملے میں ملک کو خود کفیل بنائیں گے - میں جناب اسلئیے یہ زور نہیں دیتا ہوں کہ بلکہ مجھے یہ توقع ہے کہ جو ہمارے گیہوں اور چاول کی پیداوار ہو رہی ہے اسکے حساب سے آنے والے دنوں میں اگر خدا نخواستہ کوئی ڈراؤٹ نہیں ہوا تو ہم خود کفیل ہوجائینگے ہم گیہوں میں خود کفیل رہے ہیں - پچھلے سال اور اس سال دس لاکھ ٹن گیہوں برآمد کیا ہے وہ بڑی مشکل ہے کیونکہ اس سال سو سالوں میں پہلی دفعہ بھیانک سوکھا پڑا ہے - جو کبھی آج تک ہسٹری میں نہیں ہوا - میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ ملک بچا ہے تو انہیں لوگوں کی مہربانی سے بچا ہے جن لوگوں نے ہمیں اتنی پیداوار دی نہیں تو یہاں بھی وہ ہی حالت ہوتی جو اتھوپیا یا افریقہ کے دوسرے ملکوں میں ہے - اگر میں اسی طرح سے یہ عرض کرونگا کہ اسکے ساتھ ایڈیبل آئل اور پلسیز کی بھی پیداوار ہو -

میرے پاس وقت کم ہے لیکن میں آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے کہ کسان کا بھی خیال رکھنا پڑیگا - پچھلی دفعہ اسی ہاؤس میں جناب سکھرام جی نے گیہوں اور تلہن کی قیمتوں میں کچھ آنکڑے یہاں پر پیش کئے تھے - بحث ہو رہی تھی کہ فلور ملس کا اشو پرائس کتنا ہوگا - اور انکی زبان سے ہمکو یہ پتہ چلا - منسٹر صاحب ذرا توجہ فرمائیں - کہ جہاں ہم ۱۷۳ روپئے اس غریب کسان کو دے رہے ہیں - تو ۱۹۳ روپئے ہمارا ہینڈلنگ چارجز ہوتا ہے - جو

[شری غلام رسول متو]

ایف - سی - آئی - ہینڈلنگ چارجیز اسٹور کرنے یا لانے لے جانے میں کرتی ہے وہ ۱۹۳ روپئے خرچ ہوتا ہے - اسکی طرف بھی دھیان دینا ہوگا - میں اس واسطے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ آٹا ایک کنزیومر کو کسی بھاؤ میں ملتا ہے اسمیں ۱۷۳ روپئے پرتی کوئنٹل کا خرچ جو ایف - سی - آئی - کرتی ہے وہ شامل ہوتا ہے - اگر اس خرچ میں کمی کرکے دکھائیں تو بھجن لال جی تو وہ رقم کسان کو دیدینگے - اگر ۱۹۳ میں سے ۹۰ روپئے کم کر دیں تو ۷۰ روپئے ۱۷۰ کے بجائے ۲۳۰ روپئے کسان کو دے سکتے ہیں - کیونکہ کسان ریڑھ کی ہڈی ہے - کسان ہماری تمناؤں کا موکز ہے - ہمارے لئے کسان ہی سب کچھ ہے - اور اس چیز کیلئے کسان کی طرف دھیان دینا ہوگا - میں آخر میں علامہ اقبال کے شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں کلپناتھ جی دھیان فرمائیں - اور بھجن لال جی کا دھیان بھی آکرشت کرنا چاہتا ہوں - اور علامہ اقبال کے شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں - اور وہ یہ ہے کہ :

جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی
اس کھیت کے ہر خوشۂ گندم کو جلا دو-

انہیں الفاظ کے ساتھ میں جناب بھجن لال جی سے درخواست کرونگا کہ وہ اپنے جواب میں میرے ان چند موضوعات کا تسلی بخش جواب دیں - تاکہ ملک اور قوم کو اطمنان ہو جائے - کہ ہم ایسی قوم ہیں کہ جسمیں اعتماد ہے خود اعتمادی ہے اور ہمیں جو کام کرنا چاہئے - وہ ہم کرکے دکھائینگے اور بھجن لال جی کی قیادت میں کرکے دکھائینگے۔

[دھنیہ واد -]

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ANAND SHARMA); Mr. Hari Singh. It is his maiden speech.

श्री हरि सिंह (उत्तर प्रदेश) : उप-सभाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान की आजादी का प्रस्ताव जब इंगलेंड की पार्लियामेंट हाउस आफ कामन्स में एटली ने जबकि वह प्रधान मंत्री थे, पेश किया तो दुनिया के जाने-माने प्रधान मंत्री और विरोधी दल के नेता इंगलैंड के चर्चिल महोदय ने कहा कि अगर हिन्दुस्तान को आजादी दे दी गई तो हिन्दुस्तान के इंसान को पानी पीने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा और उस देश के 35 करोड़ लोगों की मौत

का कलंक एटली साहब आपके माथे पर लग जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस बात की आवाज और चुनौती को उस वक्त के प्रधान मंत्री जी आजादी के बाद बने हमारे माननीय पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने चर्चिल के इस प्रस्ताव को इस चुनौती को स्वीकार किया और उन्होंने देश के अन्दर खेती की बुनियाद को मजबूत करने के लिए किसान को खुशहाल बनाने के लिए हिन्दुस्तान जो अपने हाथ में अनाज के लिए हमेशा कटोरा लिए फिरता रहता था और मैं कहना चाहता हूं कि आजादी के बाद में अकाल नहीं पड़े, लेकिन जब चर्चिल साहब के खानदानियों का राज रहा तब कई बार हिन्दुस्तान के अन्दर अकाल पड़ा और हजारों की तादाद में लोग मरते गए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान को जो चर्चिल का प्रोफैटिक प्रोनाउंसमेंट होता था हमारे देश के रहनुमाओं ने उस को झुठलाया और यही नहीं उसकी बुनियाद खड़ी की इस बात के लिए कि आज हिन्दुस्तान का किसान खुशाली की तरफ जा रहा है। यही नहीं हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी जिन्होंने कि "जय जवान जय किसान" का नारा दिया श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद अपने आत्म-सम्मान को कायम रखते हुए अपना आंचल अपना दामन अनाज के लिए पसारने के लिए इंकार कर दिया। तो मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान वह देश है जिसने आजादी के बाद हिन्दुस्तान में जो किसानों की और खेती में तरक्की हुई है उसका सानी ढूंढना मुश्किल है और हो सकता है आज सदन के अंदर बहुत सी शिकायतों का होना चाहिए यह तो ठीक है, लेकिन हमारा लक्ष्य बहुत दूर है उसको पता करना चाहिए। बहुत कहा गया कि चीन हम से आगे है और दूसरे मुल्क हम से आगे हैं, लेकिन आप देखिए 1947 के बाद देश में कितनी तरक्की हुई है उस का अंदाजा जो दिन भर में बहस चली है उसमें कितने आंकड़े आए हैं और आंकड़ों से मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यगण और उप सभाध्यक्ष जी आप भी ऊब गए होंगे, मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि आजादी के बाद से हिन्दुस्तान में जो किसानों की तरक्की हुई है उसको आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे खाद के बारे में, क्योंकि खाद किसान की उपज के लिए बहुत जरूरी है और सारा खाद पहले दुनिया के दूसरे देशों से आया करता था। लेकिन आज फास्फोरिक खाद का उत्पादन 8000 टन से बढ़ कर 16,65,000 टन हो गया है। सन् 1951-52 से सन् 1987-88 के बीच में देश में खाद की खपत 135 गुना बढ़ गयी है। यही नहीं, अगर आप गौर से देखें तो हमारे देश में इस समय जो दूध का उत्पादन है, वह भी बढ़ा है, जो कि सन् 1951 में पौने दो करोड़ टन था, अब चार करोड़ टन से ज्यादा हो गया है। इस तरह से आप किसी भी क्षेत्र को ले लीजिये, खेती में तरक्की हुयी है। हम आज अनाज के मामले में अपने पैरों पर खड़े हुये हैं। आज हमको कहां दूसरे देशों में दौड़ना पड़ता है कि हमको अनाज दीजिए? आज हम बहुत से देशों को अपना अनाज दे रहे हैं। राजनीतिक तौर पर भी हमको अनाज लेना पड़ता है और देना भी पड़ता है। यहां यह कहा गया कि हम दूसरे देशों से अनाज ले रहे हैं। बहुत सारे देशों से अनाज लेना पड़ता है, उसकी बहुत सारी शर्तें होती हैं, डिप्लोमेटिक शर्तें होती हैं। अपने दोस्तों को, भूखे रहकर, उनको अनाज देना भी पड़ता है और कभी-कभी लेना भी पड़ता है। आज दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है, चाहे वह कितना ही खुशहाल से खुशहाल है, चाहे अमरीका या रूस है, वह भी दूसरे देशों से अपनी खाने-पीने की चीजें, अनाज तक लेते हैं। आपको यह सुनकर

[श्री हरि सिंह]

ताज्जुब होगा कि चीन जैसा देश अमरीका से बहुत सारी चीजें ले रहा है, खाने की चीजें ले रहा है, अनाज सम्बन्धी चीजें ले रहा है । तो यह कोई ऐसी बात नहीं है, जिससे हम इतने कलंकित हो जायेंगे कि हमने थोड़ा सा बाहर से अनाज मंगा लिया है ऐसा नहीं है कि इससे देश बड़ा गिर गया है या सारी तरक्की छिप गयी है । हमारी सरकार ने किसान के जीवन को नहीं फूंका । ऐसा कोई गलत अन्दाज लगाना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है ।

यही नहीं, अगर आप देखें, हमारा जो 1988-89 का बजट पेश हुआ है उसमें किसानों के लिये तमाम सुविधायें दी गयी हैं और उससे हमारी सरकार का रुख मालूम पड़ता है । हमारी सरकार की इच्छा है कि हमारा किसान अपने पैरों पर खड़ा हो और चीन, जापान या दुनियां के जो तरक्की-याफ्ता मुल्क हैं, उनके किसान की तरह हमारा किसान हो जाय । मैं यह भी कहना चाहता हूं, वैसे हमारे वर्मा जी किसानों के बड़े करीब हैं, जानते हैं, हम भी देखते हैं किसानों के घरों में आज टेलीविजन हैं, आज वहां टेलीफोन भी पहुंचे हैं । इस तरह सारे देश में जो तरक्की हुयी है, उसे हम झुठला नहीं सकते । मैं मानता हूं, होना तो बहुत चाहिये, सारी चीजें सब जगह नहीं पहुंची हैं, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता, लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता कि कुछ हो ही नहीं रहा ।

कहा गया--निराशा का वातावरण है, किसान कर्ज में है । कर्ज में है, लेकिन उनको कर्ज से मुक्त करने के लिये हमारी सरकार ने कितनी ही स्कीम पेश की है, वह मैं आपको बताना चाहता हूं । जो किसानों को ऋण दिया जाना था, उसका सूद घटा दिया गया है, पहले यह 14 परसेंट लिया जाता था, अब इसे घटा कर 11.5 परसेंट कर दिया गया है । इस बजट के अंदर कर्जे के लिये 300 करोड़ रुपये का प्रावधान लागकर कर दिया गया है । यूरिया के प्रति बेग पर 8 रुपये 80 पैसे कम कर दिया गया । "जलधारा" एक नई स्कीम चालू की गयी । हम बाहर से जो प्रेस्टीसाइड मंगाते थे, उसमें आयात-शुल्क कम कर दिया गया । मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा जो बजट है, उसका बारीकी से अध्ययन करें, उसको देखें तो लगेगा कि यह किसानों का ही बजट है और इसने किसानों के दिलों में कितनी ही आशायें पैदा की हैं, इसका अनुमान तो किसानों में बैठ कर ही किया जा सकता है ।

महोदय, लोग सोचते हैं कि बस एक साल के अन्दर सारे देश की गरीबी दूर हो जाय, मुफलिसी दूर हो जाय, जो कि सम्भव नहीं है । जब यह प्रेक्टिकली करने चलते हैं, तो पता चलता है कितना मुश्किल है । हमारे मित्र वर्मा जी, मैं कोई लांछन नहीं लगाना चाहता, वह उत्तर प्रदेश में कृषि के मंत्री रहे हैं, कितना आगे बढ़ पाये, इसका अन्दाज खुद लगा लें । आगे भी बन सकते हैं, हम यह नहीं कह रहे । लेकिन जब सारी प्रेक्टिकल चीज आती है तो यह बहुत मुश्किल होता है ।

यही नहीं आप देखें कि पहले हमारे देश में 5 करोड़ टन अनाज पैदा होता था, अब 15 करोड़ टन से ज्यादा अनाज पैदा होता है और लक्ष्य 16 करोड़ कुछ का रहा है, गेहूं हमारा चार करोड़ टन पैदा होता है। पहले खेती 13 करोड़ हेक्टेयर में होती थी, अब 17 करोड़ हेक्टेयर में होती है। तो यह सब कुछ कहने का मतलब यह है कि हमारी सरकार का रुख हमारे देश के प्रधान मंत्री की तवज्जुह, जो हमारा देहात में किसान रहता है जो खेत में हल चलाता है उसके पसीने की ओर है और उसकी चिंता हमारे प्रधान मंत्री को है इसलिये आप देखते हैं कि आज हमारे प्लानिंग का, हमारे बजट का जो मेजर हिस्सा है वह किसान की जिन्दगी से ताल्लुक रखने वाला है। आज उनको तरह-तरह की सहूलियतें दी जा रही हैं ट्रैक्टर खरीदने के लिये, बीज खरीदने के लिये सारी सुविधायें दी जा रही हैं यह सहूलियतें इसलिये जुटाई गई हैं क्योंकि हमारा किसान मजबूत होगा तो हमारा देश भी मजबूत होगा। गरीबी तभी खत्म होगी। जब किसान की गरीबी खत्म होगी। यह सारा समाज एक-दूसरे से बहुत गहराई से, मजबूती से जुड़ा हुआ है।

तो मैं यह कह रहा था कि सरकार की सारी तवज्जुह इस बात पर है कि हमारे किसानों की गरीबी दूर हो। कहते हैं कि लोग गांव से दौड़ कर शहरों की तरफ आ रहे हैं। लोग गांवों से भाग कर शहरों की तरफ आ रहे हैं। इसका कारण यह है कि आज हमारे देश के नौजवान किसानी से डरते हैं। वे काम नहीं करना चाहते हैं वे किसानी के पेशे को हेय समझते हैं, नीचा समझते हैं।

महोदय, आज हमारे देश के कृषि वैज्ञानिकों ने खेती को मैकनाइज्ड किया है। बीज की कितनी ही नस्लें निकाली हैं। यहां तक कि जो की नीलम, केदार जैसे नए-नए बीजों की खोज की है। यह सब हो रहा है। महोदय, अभी यहां कहा गया कि बाहर से टैक्नोलोजी मंगानी चाहिये। विदेशी टैक्नोलोजी, बाहर की टैक्नोलोजी हिंदुस्तान की परिस्थिति, उसके वातावरण, उनके रहन-सहन, यहां की धरती और पानी के मुताबिक फिट नहीं बैठती है। हां, अगर कुछ आवश्यक चीजें हो तो मंगा सकते हैं आज हमारे हिंदुस्तान के साइंटिस्ट्स बड़े अनुभवी और योग्य हैं। वे सारी चुनौतियों का मुकाबला कर सकते हैं। पिछले दस-बीस साल के मुकाबले आज आप बाजार में देखें तो पायेंगे कि गेहूं की, सब्जियों की और फलों की तस्वीर बदल गयी है शिमला के सेबों की तस्वीर बदल गयी है। आज चौराहे पर सेब और अनार मिल जाता है। तरह-तरह के फल मिल जाते हैं हालांकि यह जरूर है कि सब को नहीं मिल पाते हैं। तो यह चमत्कार आया कैसे? इसलिये आया कि हमारी सरकार ने किसान को बीज पानी और दूसरे इम्प्लीमेंटस दिये हैं।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं कुछ सुझाव दे कर अपनी बात खत्म करूंगा। एक बात तो यह है कि किसान को जो सबसिडी देते हैं, इसको समाप्त कर देना चाहिये और उसके बजाय किसान को ब्याजमुक्त ऋण देना चाहिये। नम्बर दो, मैं यह कहना चाहता हूं कि एक सबसे बड़ी बात यह है कि किसान को दस हजार, बीस हजार रुपया दिया जाता है और बाद में उनकी जमीन को नीलाम कर दिया जाता है। यह नियम विरुद्ध है और हमारी डेमोक्रेसी का जो प्रिंसि-पल है, उसके खिलाफ है। यदि किसान पर तकावी का या दूसरा कर्ज है तो उनको रिकवरी के लिये हवालात में बंद कर दिया जाता है और कर्ज है तो आप उनकी चीज नीलाम कर दो लेकिन उसको हवा-लात में बंद मत करो। अब तो नियम यह हो गया है कि उसको बड़ी जेल में भेज दो। मैं कहना चाहता हूं कि यह दोनों चीजें खत्म कर देना चाहिये। आज हम देखते हैं कि किसान को जो रुपया दिया जाता है उस पर लिमिट लगी हुई है थोड़ा-सा रुपया देकर उसकी जमीन को नीलाम करना, यह नहीं होना चाहिये।

उपसभाध्यक्ष महोदय, एक और बात यह है कि बड़े-बड़े जमींदारों से जो जमीन निकली थी, उसका सही इस्तेमाल कर के उसे गरीब लोगों में नहीं बांटा गया है। अभी तक सैकड़ों मुकदमे चल रहे हैं और उनका निस्तारन नहीं हुआ है। यह जरूरी है कि इनको निकालकर देखा

[श्री हरि सिंह]

जाना चाहिए क्योंकि लोगों ने फर्जी नामों से कब्जा जमाया हुआ है और वह जमीन मजदूरों और गरीबों में बांटी जाना बहुत जरूरी है।

आखिर में दूध की बात करना चाहता हूं। दिल्ली में हमारी मिल्क स्कीम और मदर डेयरी से जो दूध दिया जाता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा मेरठ मंडल और उत्तर प्रदेश के आसपास के जिलों से आता है। यहां पर दूध की कमी है और हमारे यहां के कमजोर तबके के लोग जिन्होंने कि लोन लेकर जानवर लिए हैं, उन्होंने अपनी कोआपरेटिव सोसायटीज के जरिए विभाग में एप्लाय कर रखा है। हम एग्रीमेंट को तैयार हैं, अपना दूध देने को तैयार हैं। लेकिन हमारा विभाग उनको सुनने को तैयार नहीं है। एग्रीमेंट करने को तैयार नहीं हैं। तो यह जो कैसेज हैं, उनको डिस्पोजल करना चाहिए। सारे दूध पर कुछ मोनोपोलिस्ट्स ने कब्जा कर रखा है। हमारी सरकार जो मोनोपोलिस्ट्स हैं, जो अण्डरटेकिंग्स हैं उनको खत्म कर रही है, लेकिन दिल्ली में दूध जो सप्लाई होता है, में मोनोपोली यह हो गयी है कि उनके मुकाबले यदि कोई दूसरा आदमी आता है तो उसको वे जमने नहीं देते और मार तक देते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि दूध की जो मोनोपोली है इसको खत्म करना चाहिए। इस तरह हम किसान की और देश की हालत अच्छी बना सकेंगे। आज किसान निराशा में नहीं है और सरकार का जो रूख वह उसकी उन्नति का है। एक दिन आएगा जब हमारे देश का किसान, इस कृषि प्रधान देश का किसान दुनिया के किसानों में सबसे अव्वल दर्जे का किसान कहलाएगा। ऐसी मैं आशा करता हूं। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ANAND SHARMA): New, Mr. Chitta Basu.

SHRI CHITTA BASU (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, I would like tor intervene only because I found in the voluminous Report of the Ministry of Agriculture no mention about the missing link in the strategy of stepping up agricultural production and that missing link, if you permit me to say... *(Interruptions)* ... Mr. Vice-Chairman, Sir, at least I want your attention. They may not be interested.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ANAND SHARMA): I am.: trying to attract the Minister's attention for you.

SHRI CHITTA BASU; I think, Mr. Vice-Chairman, Sir, that mat missing link is the lack-lusture or dismal performance of the Government regarding land reforms.

I think the strategy on the basts of" which the Green Reovlution was successful has started paying diminishing returns. Anyway, I would not like *to* discuss that subject now. My only purpose of taking part in the debate at the fag end is *to* point out to the Government and to bring *to* the notice of the Members on the other side of the House who cry hoarse about land reforms only one thing. They should know what the Government has done and, what needs to be done. Now, Mr. Vice-Chairman, Sir, as you are quite aware—you are well informed, I know— the Sixth Plan had indicated the timeframe for completing the various tasks under the land reforms programme. Only two tasks I would mention no-,/ which were identified "by the Sixth Plan. One was that all the laws conferring owenrship rights on tenants ought to have been enacted by 1982-83. That was one of the tasks which was identified by the Sixth Plan. The second task which was identified that the distribution of surplus lands ought to have been completed and implemented by 1982-83. Sir, you are an informed person and I would like to ask you whether these tasks have been accomplish-, ed. The answer would be a most emphatic "No". No; these two tasks," which have been identified by the Sixth Plan, have -not been accomplished at all. Now

I would only like to state that the Sixth Plan also identified the reasons for that kind of a lack-lusture performance. I would like to quote from that document. It says like this:

"If this progress has been less than satisfactory.......... "—I mean the progress in land reforms—" it has not been due to any flaws in the policy, but due to indifferent implementation."

I want to know from the honourable Minister now whether that indifference, that indifference attitude, in respct of the main programme of land reforms has changed or is likely to change and what steps he proposes to take to bring about a change in that indifferent attitude.

So far as the importance of the land reforms programme is cocnerned, I would like to quote only a very small paragraph which has been written in the Seventh Plan:

"This question of land reforms has a vital link both in terms of the anti-poverty strategy and for modernisation and increasing the productivity in agriculture."

That is all. Therefore, that importance also was emphasised by the Seventh Plan. Now, only one point I would like to mention and that is the widening gap between the estimated surplus and the actual surplus. There is a very interesting stu4y-As far as I myself am concerned, I have noted certain facts. No. I, the 26th round of National Sample Survey estimat-ed the surplus at 4.8 million hectares. Please note, Mr. Vice-Chairman. The census in 1970-71 put the figure as high as 12.1 million hectares. Now, look at the difference. Where is 4.8 million hectares? The census of 1970-71 says that it should be 12.1 million hectares. The census in 1976-77 has brought down the figure to only 8.88 million hectares. And[1] in great contrast of all this the States themselves estimated the surplus land to be only 2.35 million hectares. I do not like to add many figures.Why this dis-crepancy? While it "was estimated to to 12.1 million hectares, ultimately all the States together estimated it to be 2.35 million hectares. Why this discrepancy? Where has the and gone? Where has the land vanished?

SHRI KALPNATH RAI:In West Bengal.

SHRI CHITTA BASU: Have patience. I will tell you. We have got patience-The surplus has been slashd by the State Governments, because most of the State Governments, if you allow me to say so, run by the Congress(I) are dominated by feudal landlords. Times does hot permit me to say ail these thinigs. There are feulal landlords who run the Government who do not like to see that land reform measures are implemented thoroughly.

Sir, he has mentioned about West Bengal, *(interruption)* I am coming t6 mat. Don't become impatient. According to the Annual Report of 1985-86 of the Ministry of Agriculture, the surplus was 2.94 million hectares. And of this declared surplus only 1.75 million , hectares was distributed. And the remaining declared surplus, namely, 149 million hectares could not be distributed. It is also to be noted that only an insignificant fraction of this, namely, 6.87 lakh hectares, is still under litigation. My question to the hon. Minister is what about the remaining surplus? Why are these surplus lands not being distributed? What is the reason? In the context of this I will say that you have all over the country distributed 1.75 million hectares. West Bengal's contribution is more than 12 lakh acres. You can understand "that next contribution is from- Kerala-. Facts cannot be denied.

Therefore from all this, facts stand out. First, the surplus has been grossly underestimated. Two. even the under-estimated quantity could not be distributed.

Sir, I complete, because I find that you are also impatient.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ANAND SHARMA): I am not impatient, but we have run out of time.

SHRI CHITTA BASU Other Members have also become impatient. They should be—as I am. Therefore, the whole question is that of political will. This political will is not there and for this reason the agricultural strategy cannot succeed. The green revolution strategy cannot remain altogether beneficial unless there is a fundamental change in the land relationship. Therefore, I have all along been stressing, in this House and in the other House, one point. I admit that the matter rests with the State Governments. But the Parliament cannot remain oblivious of the stark realities obtaining in many States. Therefore, would the Government and the hon. Minister agree that a Parliamentary Committee should be constituted to hold an inquiry and to find out the reasons for the malperformance of the State Governments in respect of the land reform measures? I would request the hon. Minister to consider the feasibility and desirability of such a committee. With these words, I conclude thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ANAND SHARMA): Mr. Narayanasamy. I would request the hon. Members to be brief.

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, कृषि पर बहस हो रही हैं और विरोधी दल का एक भी नेता यहां मौजूद नहीं है। इनका देश की जनता से क्या संबंध है। ये जनघाती हैं, देशघाती हैं।

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : यहां खाली आपकी बकवास सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। मेरा कहना यह है कि जो दो स्पीकर रह गये हैं वे कल बोल लें और उसके बाद मंत्री महोदय जवाब दे दें।

श्री कल्पनाथ राय : यह विरोधी के दल नेता किसानों के दुश्मन हैं।

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : सबसे बड़े दुश्मन तुम हो। आप खाली नाम के लिए बुलवाना चाहते हैं तो अलग बात है।

उपसभाध्यक्ष (श्री आनन्द शर्मा) : जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का निर्णय है उसके मुताबिक हम को चलना हैं। यह तय किया गया था कि इस पर चर्चा आज ही समाप्त होगी और कल केवल मंत्री महोदय अपना उत्तर देंगे। थोड़े समय की बात है।

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : 8 बजने में बीस मिनट बाकी हैं और दो स्पीकर बोलने बाकी हैं।

श्री कल्पनाथ राय : हिन्दुस्तान की कृषि पर, किसान पर बहस हो रही है और जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, लोकदल का एक भी सदस्य मौजूद नहीं है। ये किसान के दुश्मन हैं।

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : आप में हिम्मत नहीं है कि इस सब्जेक्ट पर दो दिन तक बहस करा सकें।

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, the history of agricultural development in, this country can be judged from political and socio-economic angles. Right from the days of Independence, our Congress Government started the green revolution in the country. It was during the period of our great leaders Pandit Jawaharlal Nehru and Shastri Ji. When our great leader, Mrs. Gandhi, came into power, she started the green revolution in the country in a vigorous manner. Sir, i may tell you that many leaders from the Opposition have opposed Shrimati Indira Gandhi's policy of green revolution. She took up tbk challenge. She called the scientists and told them very frankly that this country needs green revolution and that the country can prosper only through the green revolution. Sir, now we are enjoying the benefits of the green revolution which was started by the Congress Party.

Sir, in 1985-86, our agricultural production was 150 million tonnes. It was the target fixed and it was achieved. This is the history which was created by the Congress Party relating to agricultural production. Sir, in the 7th' Plan, the target fixed was 160 million tonnes. But we could net achieve the target because of natural calamities in the country. Sir, you have seen the drought in Gujarat and Rajasthan and floods in Assam, West Bengal and Bihar. Sir, drought affected 75 per cent of our cultivable area and the remaining 25 per cent was affected by the floods. In spite of that, we have seen in the country that there is not even a single starvation death which is the achievement of the Congress Party. But the Opposition leaders are telling about the land reforms. Sir, I may tell you that in our country, the land reforms policy has been fully pursued by this Government. In fact, we been distributing the surplus land to the landless labourers and agricultural lab-ourers. Sir, a lot of cases have been locked up in the,courts on procedural facts about which the Government cannot do anything because land reforms Act provide the legal remedy to the person who is aggrieved. Therefore, we could not pursue k more vigorously. In spite of it, we have taken it as a vow that this Gov-ernment will implement the land reforms policy with full spirit and vigour. That is our Congress Party's policy which was announced by our Prime Minister in political resolution recently.

Sir, coming to the other aspects of our agricultural production, in this year's Budget, as you have[1] seen, 65 per cent of the budget has been allocated for agriculture alone. Agriculture has been given the importance. In the past two years agriculture was not given much importance and we have seen the results. This year we have woken up and we have taken up the task of increasing the agricultural production by all means. Sir, 14 States have been selected for the purpose of in-creasing the agricultural production. An by the we can definitely achieve the target because all the State Governments have been given the fillip by our Prime Minister and the Agriculture Minister by callng them periodically and giving them instructions to implement the policies of the Government of this country.

Sir, water management should not be. under the control of the Ministry of Water Resources alone. I would like to say that it should be a joint venture by the/ Agriculture Ministry and the Water Resources Ministry because water is the maim source for the purpose of increasing the agricultural production. But the Water Resources Ministry is functioning independently and the Agriculture Ministry is also functioning independently and there is no coordination. Even if there is coordination, we find that some particular projects which have been envisaged for the purpose of irrigating the land or for giving drinking water to the people are locked up in disputes. We find there is the Cauvery waters dispute between Kar-nataka and Tamil Nadu and my State of Pondicherry. There is the Telugu-Ganga project dispute between Andhra Pradesh, and Tamil Nadu. Now, our Prime Minister has taken a very clear view and said that water is a national subject and it should not be the property of any State. Now, a line has been drawn by the Government that water is a national. subject and it should be utilised by the States wherever it is required and whenever it is required. Therefore, I welcome this decision taken by the Government in this decsion taken by the Government in this regard.

Sir, there is another aspect of lab to land policy in regard to inventions made by our scientists. Sir, scientific inventions are made: scientific innovations are made and they reach the farmers and they are getting the benefits. But, I find, Sir, that to sending our technology, our scientific inventions to the fanners, there is a lack! * of coordination. I would like to submit that the universities and the public sector undertakings are making inventions rela-ting to large scale production of seeds and a variety of crops. And when they reach the farmers, they become outmoded. I would like to submit to the hon. Minister to take up the task of bringing the inventions to the farmers within a short span of time. Sir, our young and energetic

*

[Shri V. Narayanasamy] Minster is here. I hope he will take the task of doing it within a short period. The hon. Minister of Fertlizer is doing his best for the agricultural farmers. Farmers are prepared to receive the new technology. But we find that the agricultural officers are sitting in their offices.' They are not giving proper education to -the agriculturists. It is happening in all States, *bi* they Congress (I) ruled or Opposition ruled States. They are only doing burea-cratic work. They are not going to the fieds or to the village worker for the purpose of giving him the benefits. The officers are doing bureacratic work. This tendency should be curbed. Fertilizer production is on the increase. The other benefits which we are going to give to the agriculturists are subsidies. For a 50 kg bag of fertilizer urea the Government has given a subsidy of Rs. 8.80 to the farmer. These are the achievements of the Government. These are the incentives to the farmers to increase agricultural production.

Therefore, Sir, I congratulate the Agriculture Ministry and I hope that we will be able to achieve the target in agricultural production whether it is in the form of crops or oilseeds or pulses. With these words, Sir, I conclude. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AN AND SHARMA): Yes, Mr. Subas Mohanty, please take Ave minutes only.

SHRI SUBAS MOHANTY (Orissa): Sir, I have to make some important points, kindly give me a little,more time.

Mr. Vice-Chairman, Sir today it has become-.absolutely necessary to have a fresh look towards the agricultural sector which occupies an important place, in the Indian economy. In spite of the sincere efforts of the Government to meet, the challenges posed by. the recent droughts, much is desired-to be Jane in Indian agriculture and thereby ameliorate the condition of the rural .poor who constitute the bulk of population of the country. Unless the overall situation of the agricultural labourers, small farmers and. marginal fanners is changed, it; is doubtful if any of the developmental activities would be effective in rural areas. Of course, a lot has been made of the higher allocation to agriculture in this year's budget. It has been raised by 40 per cent over the last year's budget. Though it works impressive, but considering the rate of inflation, the long neglect of agricultural sector in the past and the immediate need to improve *it,* one can only wish the so-called high allocation can adequately meet the national need.

It has been the .endeavour of the Government to improve the level of agricultural production. This needs various inputs like land, seeds fertilisers, water, labour and agricultural equipments etc. The better utilisation of these factors can improve the agricultural production. But the prices of all agricultural inputs has risen beyond the farmers' reach as compared to prices of agricultural produce, which has completely shattered the farm economy. The expenditure incurred by the. farmers on account of fertilisers, irrigation charges, electricity, pesticides, insecticides, diesel and oil etc. has increased manyfold.

Sir, the growth of Indian agriculture is basically a story of growth in- foodgrain production. Tn terms of volumes, the achievement is significant. But, it is obvious that the farmers are not getting remunerative prices for their produce so as to be adequately compensated for the increase in prices they are required to pay for producing the foodgrains. Moreover, Government procurement scheme hardly covers anything beyond rice and wheat and that too; the Government procures 15 per cent or less of the produce -It deprives the large section of , small and marignal farmers of -the benefit of higher procurement prices.

It is well known that our agriculture is still too much dependent on irregular monsoon. But considering the severity of last drought,the budgetary allocation of Rs.. 227 crores, for water resources is hardly adequate to spread irrigation to the areas which are at present rainfed. Without adequate facilities of irrigation, production as- desired cannot be achieved. Of course,, a new thrust has been given for

the overall improvement of agriculture in the country with a number of beneficial measures for the farming community. The problem of the farmers need to be sorted out as a first priority. The higher allocation in this year's budget for agriculture should be continued in years ahead.

The present drought situation has also brought into light some of the basic weaknesses of our agriculture and the imbalance in cropping pattern. Those are *to* be given a serious thought in the coming years. The prices of agricultural-produce should be directly, related to the input costs safeguard the farmers' interest.

Since the severe drought condition in major parts of the country "has very adversely effected the economic position of the farmers, the farmers' credit interest should not exceed 6 per cent and practice of charging compound interest by commercial banks and land development banks should be stopped forthwith.

Crop insurance scheme in its present form is not also beneficial to the farmers. It should be made more realistic and effective. Moreover, the scheme should apply to all crops grown by the farmers-Farmers- are not getting adequate prices for their produce due to extremely limited network of procurement. The unavailability of the benefit of procurement prices will lead to failure of agricultural pricing policy.

In the interest of reducing cost incidence, the input prices must be lowered so that there is a net increase in value addition. The improved farm implements, better quality seeds, better post-cropping and post-harvesting technique and better farm management knowledge should be given to farmers.

Lastly, I want to mention that unless the progress of farming community is ensured, our march towards the 21st century, wilt be greatly hampered.

डा० गोविन्द दास रिछारिया (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, देश में स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने एक काम पूरा कर दिया हरित क्रांति कर के। हमारे देश के किसानों ने, अनुसंधानकर्ताओं ने और कृषि के विशेषज्ञों ने मिल कर देश में हरित क्रांति पैदा की और आज हमारा राष्ट्र भोजन के मामले में स्वावलम्बी बन गया है। उसी के साथ दूसरा काम प्रारंभ हो गया है जिसे श्वेत क्रांति कहते हैं या जिसे हम दूध में स्वावलम्बन कहते हैं। उसके लिए भारत सरकार ने कार्य प्रारंभ किया है। सन् 1954 से सारे देश का सर्वे किया गया और हमारे विशेषज्ञ इस फैसले पर पहुंचे कि राष्ट्र में चारे का अनुसंधान किया जाए और 1962 में भारत सरकार ने चारा अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की। चारा अनुसंधान केन्द्र में बड़े-बड़े विशेषज्ञों ने कठिन परिश्रम कर के चारे की इस तरह की किस्में निकाली है इस तरह से अनुसंधान किया है उनका यह दावा है कि कोई भी किसान एक एकड़ जमीन में चारा पैदा कर के दूध के द्वारा ज्यादा आर्थिक लाभ ले सकता है बजाय गेहूं के या दूसरी फसल के। इस तरह का कार्य हमारे राष्ट्र के विशेषज्ञों ने चारा अनुसंधान केन्द्र में अपने नये आविष्कारों के द्वारा किया है और इस चुनौती को भी स्वीकार करने के लिए तैयारी शुरु कर दी है। मेरा कृषि मंत्री जी से यही निवेदन है कि अब आवश्यकता इस बात की है कि वे देश के सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को तथा राज्यों के कृषि मंत्रियों को बुला कर के उनकी एक बैठक करें क्योंकि समन्वय नहीं है। जितना अच्छा कार्य चारा अनुसंधान केन्द्र में हो रहा है आपकी प्रांतीय सरकारें उनको ग्रहण नहीं कर पा रही हैं उनको अपने किसानों तक पहुंचा नहीं पा रही हैं। मेरा कृषि मंत्री जी से अनुरोध है कि वे शीघ्र ही बैठक कर के समन्वय स्थापित करें और उनको यह स्पष्ट कर दें कि चारा अनुसंधान विभाग या केन्द्र ने जितना अच्छा रिसर्च किया है उसको आप किसानों तक पहुंचा दें, हर गांव तक

[श्री गोविन्द दास रिछारिया]

पहुंचा दें। जिस तरह से आपने गेहूं के नये बीच पहुंचा दिये थे, जिस तरह से आपने धान के नये बीज पहुंचा दिये थे और उसके बाद दालों और तिलहनों के बीज भिजवा दिये थे इस तरह से आप चारे के बीज हर किसान तक भिजवा दें। आप उनको अनुदान दें और हर प्रदेश में इस तरह के सेंटर खोलें जहां चारे के बीज पैदा किये जा सकें। इसके लिए भी हम अपने प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने किसानों के रिसर्च कार्यों के लिये भी एक नया मंत्रालय खोला है और अब विशेष ध्यान दिया जाने लगा है उस मंत्रालय के द्वारा रिसर्च कार्यों के ऊपर। तो इस तरह से हमारे राष्ट्र के किसानों के लाभ के लिए कमर कस कर भारत सरकार तैयारी कर रही है और जल्दी से जल्दी श्वेत क्रांति में भी सफलता मिलेगी। इस सफलता में हम किसानों का योगदान ले सकें इसके लिए आप अपने सभी विभागों को चाहे वह प्रदेश के कृषि विभाग हो, चाहे पशुपालन विभाग हो, चाहे डेरी विभाग हो, चाहे आपका प्लानिंग विभाग हो, चाहे आपके ब्लाक स्तर के कार्यकर्ता हों हर एक को आप लगा दें इस बात में कि वह किसानों तक जो आपके यहां रिसर्च हो रही है श्वेत क्रांति के लिए चारे के अन्तर्गत उसको वहां तक पहुंचाये। इससे आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। आपने समय कम होने पर कभी मुझे समय दिया इसके लिए हम आपका आभार प्रदर्शित करते हैं और धन्यवाद करते हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ANAND SHARMA): The discussion is over. The Minister will reply to the discussion tomorrow.

Now, the House stands adjourned till 11-00 A.M. on Tuesday, the 3rd May, 1988.

The House then adjourned at fifty-seven minutes past seven of the clock till eleven of the clock on Tuesday, the 3rd May, 1988.

MGIPMRND—349—R,S.—RS. 1—8-9-88.